वर्ष : 16 ❖ अंक : 187 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
बुधवार, 16 फरवरी 2022

आशीष की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती : टिकैत 3
गर्मी को भाप बनाकर उड़ा देंगे नतीजे : अखिलेश यादव 8

सिक्किम में कोविड के 20 नए मामले, एक की मौत

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 15 फरवरी । सिक्किम में सोमवार को कोविड के लिए 465 नमूनों की जांच की गई जिनमें 20 कोविड मामले दर्ज किए। राज्य की कोविड सकारात्मकता दर 4.3 प्रतिशत रही। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी।

जिलेवार कोविड रिपोर्ट में नौ मामले पूर्वी जिले से, सात मामले पश्चिमी जिले से, तीन मामले पश्चिमी जिले से और एक मामला उत्तरी जिले का था। सोमवार को कोविड से 56 लोग ठीक हुए। वर्तमान में राज्य में कोविड-19 के 312 सक्रिय मामले हैं। इनमें आठ मरीजों में मध्यम और 11 मामलों में गंभीर लक्षण दिख रहे हैं।

एसटीएनएम अस्पताल से एक और कोविड की मौत की सूचना मिली। मृतक पूर्वी जिले का 70 वर्षीय पुरुष था। इसके साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 440 पहुंच गई है। फिलहाल यहां के अस्पतालों में 43 कोविड मरीज भर्ती हैं। उनमें से 11 मरीज आईसीयू में हैं, स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया।

एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स व रूफटॉप फार्मिंग के शुभारंभ को लेकर तैयारी बैठक सम्पन्न

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 15 फरवरी । कृषि, बागवानी और पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा मंत्री लोक नाथ शर्मा ने 22 फरवरी, 2022 को आयोजित होने वाली एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और रूफटॉप फार्मिंग के शुभारंभ के लिए एक तैयारी बैठक की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे।

बैठक में कृषि सचिव रिंजिंग सी. भूटिया, बागवानी सचिव बीबी सुब्बा, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा सचिव डॉ. पी. सैंथिल कुमार, सीईओ सिक्किम जैविक खेती विकास एजेंसी (एसओएफडीए) डॉ. एस अंबालागन, प्रधान निदेशक, अतिरिक्त निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान, मंत्री शर्मा ने एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और रूफटॉप खेती पर व्यापक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता और बड़े पैमाने पर कृषक समुदाय को इसके लाभों पर प्रकाश डाला। राज्य सरकार प्रति इकाई क्षेत्र में उच्चतम स्तर की आय उत्पन्न करने के उद्देश्य से उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स की मिट्टी मुक्त खेती की नई पद्धति शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अधिकारियों को एक समिति गठित करना का भी निर्देश दिया ताकि कार्यक्रम शुरू होने के बाद गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए एक पूर्ण कार्य तंत्र तैयार किया जा सके।

इसके अलावा, सचिवों और अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई के निष्पादन के संबंध में अपने सुझाव दिए।

बैठक में विस्तृत घटकों को भी तैयार किया गया ताकि कार्यक्रम को आम जनता के लिए अधिक शिक्षाप्रद और सूचनात्मक बनाया जा सके।

राज्यपाल ने बुजुर्गों में किया कम्बल का वितरण

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 15 फरवरी । आज सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने पूर्व जिले के राकदुंग तिनतेक गुंपा के समीप ली आल ओल्ड एज होम के कार्यक्रम में उपस्थित रहकर बुजुर्गों में कम्बल वितरण किया। कार्यक्रम में तिनतेक ली आल संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासन एवं पुलिस विभाग के अधिकारी, अन्य सदस्य, ग्रामवासी आदि उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने सभा को संबोधित करते हुए ली आल संघ के उत्तम कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे असहाय लोगों की निःस्वार्थ सेवा करना, मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। आगे उन्होंने संघ के लिए हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन देने के साथ 51 हजार रुपये प्रदान करने की भी घोषणा की।

राजभवन में सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद पूर्वी सेना कमान के सेना प्रमुख ले जनरल आरपी कलिता, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएमवीएसएम के साथ पूर्वी कमान के वरिष्ठ अधिकारियों से औपचारिक मुलाकात करते हुए। इस मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई।

बेंगलुरु और उडुपी सहित कर्नाटक के 9 जिलों में धारा 144 लागू

रैली, प्रदर्शन, भाषण समेत कई चीजों पर पाबंदी

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एजेंसी)। कर्नाटक में हिजाब विवाद अभी थमा नहीं है। राज्य की बसवराज बोम्मई सरकार ने अब तुमकुरु जिले में भी धारा 144 लगाने का ऐलान किया है। यहां कॉलेजों के दोबारा खुलने के बाद एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। प्रशासन की कोशिश है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास किसी भी तरह की हिंसा को रोका जाए। राज्य में अब तक कुल 9 जिलों में धारा 144 लगाया जा चुका है।

यह आदेश सभी शैक्षणिक संस्थानों से 200 मीटर की दूरी पर लागू होगा। इससे पहले उडुप्पी जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाते हुए कहा था कि 19 फरवरी तक सभी क्षेत्रों में स्थित हाई स्कूल के आसपास यह नियम लागू रहेगा। जिन जिलों में धारा 144 अब तक लगाया जा चुका है उनमें- बगलकोट, बेंगलुरु, चिक्काबालापुरा, गडक, शिमोगा, मैसूर और दक्षिण कर्नाटक शामिल हैं।

कर्नाटक सरकार ने सभी तरह की रैलियों और प्रदर्शनों को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा स्लोगन चिपकाने, गाना बजाने और भाषण देने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने ऐलान किया था कि सभी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज और डिग्री कॉलेज जो हिजाब को लेकर प्रदर्शन के दौरान बंद हुए थे वो 16 फरवरी से खुल जाएंगे। किसी भी तरह के विवाद को रोकने के लिए कई शहरों और स्कूलों के नजदीक पुलिस बल की तैनाती की गई है।

मंगलवार को शिवमोगा के एक स्कूल में बुर्का पहनकर आई एक छात्रा को हिजाब हटाने को कहा गया तो उसने परीक्षा देने से इनकार कर दिया। लड़की ने संवाददाताओं से कहा, 'हम बचपन से हिजाब पहनते आए हैं और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मैं परीक्षा नहीं दूंगी और घर जाऊंगी।' इसी तरह चिक्कमगलुरु जिले के इंदवार गांव के एक सरकारी स्कूल में हिजाब पहनकर आई मुस्लिम लड़कियों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया और वापस भेज दिया गया। इसके बाद उसके माता-पिता स्कूल पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया।

उन्होंने जबरन स्कूल परिसर में घुसकर नारेबाजी की और कहा कि उन्हें अदालत का आदेश लिखित रूप में चाहिए। विरोध प्रदर्शन तेज होने पर एक अन्य छात्र ने अपने स्कूल बैग से भगवा स्कार्फ निकाल लिया। छात्र ने शिक्षकों के निर्देश पर स्कार्फ वापस बैग में रख लिया। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रधानाध्यापिका ने दिनभर के लिए स्कूल बंद कर दिया। चिक्कमगलुरु के अन्य संस्थान में हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश नहीं दिए जाने पर तनाव पैदा हो गया।

तुमकुरु जिले के एसवीएस स्कूल में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को, हिजाब पहनकर आने पर वापस लौटा दिया गया, जिसके बाद माता-पिता ने स्कूल परिसर में हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर, अदालत के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें शांत किया।

इस बीच, उडुपी जिले में छात्राओं के अभिभावकों ने मौलाना आजाद हाई स्कूल के सामने प्रदर्शन कर हिजाब पहनने वाली छात्राओं को अलग कमरे में बैठाने के अधिकारियों के निर्णय का विरोध किया। प्रदर्शनकारी अभिभावकों ने छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षाओं में बैठने देने की मांग उठायी। साथ ही अभिभावकों ने अधिकारियों से कहा कि अगर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी गई तो वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे।

कर्नाटक सरकार ने जोर देते हुए कहा है कि वह हिजाब विवाद पर उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक एवं सदन में पार्टी के उप नेता यू.टी. खादर द्वारा हिजाब विवाद का मुद्दा उठाये जाने पर यह कहा। कांग्रेस सदस्य ने अदालत के आदेश को जमीनी स्तर पर लागू करने के दौरान भ्रम की स्थिति और इसकी व्याख्या को लेकर चिंता प्रकट की।

कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जे. सी. मधुस्वामी ने सरकार की ओर से कहा, ''खादर द्वारा उठाये गये मुद्दे पर शिक्षा मंत्री जवाब देंगे, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार अदालत का आदेश लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।''खादर ने हिजाब विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि आजकल शैक्षणिक संस्थानों में स्थिति दुखद है और चूंकि यह विषय अदालत के पास है, वह इसके विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं।

कक्षाओं के भीतर हिजाब पहनने को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के कारण बंद रहे कर्नाटक के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के खुलने से एक दिन पहले राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि प्राधिकारियों को उन धार्मिक संगठनों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जो समाज को तोड़ने और छात्रों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं।

मंत्री ने एक बयान में आरोप लगाया, ''कुछ धार्मिक संगठन समाज को विभाजित करने के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं।... उनकी पहचान करने और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।''

उन्होंने दावा किया कि सभी नहीं, अपितु कुछेक छात्राएं इस बात पर जोर दे रही हैं कि उन्हें हिजाब पहनकर स्कूल जाने की अनुमति दी जाए। ज्ञानेंद्र ने दावा किया, ''मेरा मानना है कि यह (हिजाब पहनने की मांग करना) उनकी (छात्राओं की) अपनी सोच नहीं है। हमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का सम्मान करना चाहिए और उसी के अनुसार कदम उठाना चाहिए।''

सीएम के पिता के निधन पर मानव उत्थान सेवा समिति ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 15 फरवरी । सिक्किम सरकार के मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) के पिता कालू सिंह तमांग के निधन पर मानव उत्थान सेवा समिति, सिक्किम ने आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। राजधानी गंगटोक तिब्बत पथ स्थित सम्भाला आश्रम में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में गंगटोक नगर पालिका के उप मेयर छिरिंग पाल्देन भूटिया विशेष रूप से उपस्थित थे। मानव उत्थान सेवा समिति, सिक्किम दार्जिलिंग हिमाली प्रान्त के प्रभारी महात्मा अखिलेश बाईजी, सिक्किम राज्य समिति के वरिष्ठ सलाहकार महात्मा ज्ञान बाईजी, तहसिल प्रभारी सन्त महात्मा, राज्य समिति के केन्द्रीय कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य लोग उपस्थित थे।

उपस्थित सन्त महात्माओं ने कालू सिंह तमांग के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए, अपने शोक सम्बोधन में उनके निधन पर सिक्किम समाज ने एक बुजुर्ग अनुभवी अभिभावक को खो दिया है। उन्होंने कामना की कि स्वर्गीय तमांग की आत्मा ईश्वर के चरण में स्थान प्राप्त करें और स्वर्ग में सदैव उनका वास हो। उन्होंने कहा कि मृत्यु, जीवन का एक अकाट्य सत्य घटना है। संत-महात्माओं ने उनकी ओर से समाज के लिए किए गए काम को जीवित रखने का आग्रह किया।

इसी प्रकार इस श्रद्धांजलि सभा में उपमेयर छिरिंग पाल्देन भूटिया ने मुख्यमन्त्री के पिता स्वर्गीय कालूसिंह तमांग की आत्मा की चिर शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजन करने पर मानव उत्थान सेवा समिति, सिक्किम के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि कालू सिंह तमांग के निधन से सिक्किम ने वास्तव में एक सच्चा अभिभावक खो दिया है। उन्होंने भी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इससे पहले उपमेयर के साथ ही सम्पूर्ण सन्त-महात्माओं तथा अन्य लोगों ने स्वर्गीय कालू सिंह तमांग की तस्वीर के आगे फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर 108 दीप भी जलाए गए।

डॉ. वीणा बस्नेत ने की किरेन रिजिजू से मुलाकात

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 15 फरवरी । हाम्रो सिक्किम पार्टी (एचएसपी) की अध्यक्ष डॉ. वीणा बस्नेत ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की।

उन्होंने उल्लेख किया कि बैठक फलदायी रही जिसमें उन्होंने सिक्किम राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

यह जानकारी पार्टी की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। एचएसपी ने कहा कि डॉ. वीणा बस्नेत ने रिजिजू का भी आभार व्यक्त किया, जो हमेशा सिक्किम और सिक्किम के मुद्दों के समर्थक रहे हैं और उन्होंने राज्य और इसके लोगों के लिए निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।

पश्चिम जिले की वन हेल्थ कमेटी की पहली बैठक सम्पन्न

अनुगामिनी नि.सं.

गेजिंग, 15 फरवरी । पश्चिम जिले में यूएनडीपी इंडिया की ग्रीन रिकवरी इनिशिएटिव के तहत, पश्चिम जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचित वन हेल्थ मैनेजमेंट कमेटी की पहली समीक्षा बैठक जिला प्रशासनिक केंद्र के सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई थी।

सिक्किम में, ग्रीन रिकवरी पहल हरित ऊर्जा और एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के पहलुओं पर केंद्रित है। वन हेल्थ इनिशिएटिव जूनोटिक रोगों के प्रबंधन को बढ़ाने के लिए है और यूएनडीपी और सिक्किम की राज्य सरकार द्वारा ग्रीन रिकवरी इनिशिएटिव के तहत चल रहे जीओओआई-जीईएफ-यूएनडीपी सिक्योर हिमालय परियोजना के अभिसरण में कार्यान्वित किया जा रहा है।

बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर पश्चिम श्री कर्मा आर बोनपो ने की, जिन्हें समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया और समिति के अन्य अधिसूचित सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया। प्रारंभ में, श्री बोनपो ने उक्त पहल के तहत इस तरह की सहायता प्रदान करने के लिए यूएनडीपी इंडिया को धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने यूएनडीपी को एक स्थायी पर्यटन नीति बनाने का सुझाव दिया।

उन्होंने उस परियोजना पर जोर दिया जो संबंधित विभिन्न हितधारकों की क्षमताओं को मजबूत करने और समयबद्ध तरीके से अपेक्षित आउटपुट लाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि हमें पर्यटन स्थल पर कृषि-पर्यटन की जरूरत है जहां स्थानीय हितधारक अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों का प्रचार, प्रदर्शन और बिक्री कर सकें।

इसके अलावा, उन्होंने दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के आकलन के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला और कहा कि पौधों में रोगों के अध्ययन की भी आवश्यकता है, बीजों का परीक्षण करने की आवश्यकता है क्योंकि फसल की पैदावार दिन-ब-दिन घटती जा रही है। इसके अलावा, उन्होंने पौधों की बीमारियों को लेकर अनुसंधान का सुझाव दिया और इसके लिए संस्थागत समर्थन की भागीदारी के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पौधों की बीमारियों को नियंत्रित करने की जरूरत है और उत्पादकता को और बढ़ाना चाहिए।

यूएनडीपी के प्रतिनिधियों ने योक्सम में पीएचसी के सौरकरण, पशु चिकित्सा कार्यालय, योक्सम की सहायता प्रदान करने, दो सौ से अधिक हितधारकों के साथ जूनोटिक रोगों पर जागरूकता अभियान चलाने और विभिन्न ज्ञान उत्पादों का निर्माण करने सहित पहल की प्रगति पर एक सिंहावलोकन प्रस्तुत की। आने वाले महीनों में प्रस्तावित गतिविधियों पर भी विस्तार से चर्चा की, जिसमें वन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य के फोकल विभागों के अधिकारियों और फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए जूनोटिक रोगों का पता लगाने और प्रबंधन पर दो चरण का प्रशिक्षण शामिल है। यूएनडीपी द्वारा बैठक में स्वास्थ्य पहल पर एक लघु वीडियो भी दिखाया गया। बैठक के दौरान, एक इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किया गया जिसमें सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मेरी हत्या कराना चाहते हैं सीएम : राजभर

लखनऊ, 15 फरवरी (एजेन्सी)। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर उन्हें जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

यह आरोप ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान सोमवार को वकीलों के कड़े विरोध का सामना करने के बाद आया है।

भाजपा ने इस दावे को खारिज किया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे ही राजभर वाराणसी के शिवपुर में अरविंद का नामांकन दाखिल करने के लिए एक अदालत पहुंचे, कई वकीलों ने 'जय श्री राम' के नारे लगाए और एसबीएसपी नेताओं को पीटा।

एसबीएसपी ने चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है।

राजभर ने कहा कि उनमें से कुछ ने उन्हें गालियां दीं। जवाब में राजभर के समर्थकों ने जय अखिलेश के नारे लगाए।

नामांकन दाखिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने जिला निर्वाचन अधिकारी से सुरक्षा की मांग की।

मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए, ओम प्रकाश राजभर ने कहा, 'जब शिवपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा-एसबीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार अरविंद अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे, तो भाजपा के गुंडे पहले से ही काले कोट में मौजूद थे। उन्होंने मुझे और उम्मीदवार को गालियां दीं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से हम दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली आदि मुद्दों पर सपा गठबंधन को वोट देकर भाजपा को हर गांव से दूर भगा रहे हैं।'

उन्होंने आगे कहा: 'मैं मांग करता हूं कि चुनाव आयोग ऐसे गुंडों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे।' उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को हटाने की भी मांग की।

सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसरो के साथ बैठक करेगा गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एजेंसी)। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से द्वीप और सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय (एमएचए) जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ एक बैठक आयोजित करने वाला है, ताकि अंतराल को दूर किया जा सके और सीमावर्ती द्वीप क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके।

सूत्रों ने कहा कि बैठक के दौरान, एमएचए अधिकारी उत्तरी, पूर्वी सीमा और द्वीप सुरक्षा पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (स्पेस टेक्नोलॉजी) का उपयोग करके सुरक्षा अंतराल को कम करने के लिए बेहतर सीमा प्रबंधन के तरीकों पर चर्चा करेंगे।

एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा कि सीमा पर कई बिंदु (ख़वाइंट्स) हैं, जो उत्तरी और पश्चिमी सीमा में पहाड़ी इलाकों और नदी के किनारे के कारण उत्तरी सीमा पर पूरी तरह से बंद नहीं हैं यानी वहां कोई बाड़ नहीं लगाई जा सकी है। इसके अलावा चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा को ठीक से सीमांकित और परिभाषित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सुरक्षा बलों की वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर बेहतर नजर होगी। सूत्रों के अनुसार, सीमा प्रबंधन में आवश्यक तकनीक की आवश्यकता को समझाने के लिए इसरो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे सीमा सुरक्षा बलों के उच्च अधिकारी भाग लेंगे।

सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने कहा कि उत्तर और पूर्वी थियेटर्स में दोनों शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों (चीन और पाकिस्तान) पर नजर रखने के अलावा, इन कठिन इलाकों में उचित संचार प्रणाली की कमी, सीमा सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती है। यह कहते हुए कि वे पूरी तरह से रेडियो संचार पर निर्भर हैं और ऊंचाई और खराब मौसम के कारण रेडियो संचार की अपनी सीमाएं हैं, उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ बल संचार के लिए उपग्रह टेलीफोन का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें दुश्मन बलों द्वारा अवरोधन (इंटरसेप्शन) की संभावना भी होती है।

17 जनवरी, 2019 को, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा प्रबंधन में सुधार के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग को लेकर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एमएचए द्वारा बनाई गई एक टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट को मंजूरी दी। संयुक्त सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में और बीएसएफ, अंतरिक्ष विभाग और सीमा प्रबंधन प्रभाग के सदस्यों की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने बॉर्डर गार्डिंग फोर्स (बीजीएफ), इसरो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) और रक्षा मंत्रालय (एमओडी) सहित सभी हितधारकों से परामर्श किया। इस दौरान द्वीप विकास, सीमा सुरक्षा, संचार और नेविगेशन, जीआईएस और परिचालन योजना प्रणाली और सीमा बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

टास्क फोर्स ने यह भी सिफारिश की है कि सीमा सुरक्षा बलों की तत्काल आवश्यकता को उच्च रिजॉल्यूशन इमेजरी की खरीद और संचार के लिए बैंडविड्थ को शामिल करके पूरा किया जाए, जबकि इसरो एमएचए के विशेष उपयोग के लिए एक उपग्रह लॉन्च करेगा।

बीएसएफ को अभिलेखीय सुविधाओं की स्थापना सहित ग्राउंड सेगमेंट और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यान्वयन के लिए अग्रणी एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। दूरदराज के इलाकों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती को भी उपग्रह संचार द्वारा समन्वित किया जाएगा, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (आईआरएनएसएस) आधारित जीपीएस उच्च ऊंचाई, दूरस्थ और कठिन सीमाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में परिचालन दलों के लिए नेविगेशन सुविधाएं प्रदान करेगा।

सीएम धामी का 60 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा

देहरादून, 15 फरवरी (एजेंसी)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दावा किया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस बार 60 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी।

धामी ने विजय चिह्न 'वी' बनाते हुए दावा किया कि राज्य में भाजपा ही अगली सरकार बनायेगी।

राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों पर सोमवार को हुए मतदान के एक दिन बाद धामी ने यहां राज्य पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, आप 10 मार्च आने दीजिए। आप देखेंगे कि हम 60 (का आंकड़ा) पार कर लेंगे।

राज्य में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 57 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार उसने चुनाव में अबकी बार, साठ पार का नारा दिया था। चुनाव परिणाम 10 मार्च को आएंगे।

हाल में वायरल की गई एक कथित खनन वीडियो के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पिछली सरकारों ने प्रदेश में खनन का दोहन किया और खनन माफियाओं को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता यह देख रही है कि किसने क्या किया।

मुख्यमंत्री धामी काफी देर तक ढोल की थापों के बीच मुस्कराते और बार-बार 'वी' का विजय चिह्न दिखाते रहे। उनके साथ भाजपा की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान, राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी थे।

इस बीच कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश से भाजपा सरकार की विदाई हो रही है और कांग्रेस सत्ता में आ रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में से कम से कम 48 पर विजय हासिल करेगी।

कांग्रेस को झटका, अश्विनी कुमार ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली, 15 फरवरी। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज सुबह इस्तीफा भेजा और कहा कि वह पार्टी से बाहर रहकर देश के लिए बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। उन्होंने अपने त्यागपत्र में कहा, मैं 46 वर्षों के लंबे जुड़ाव के बाद पार्टी से अलग हो रहा हूं और आशा करता हूं कि ऐसे परिवर्तनकारी नेतृत्व से प्रेरित होकर जनता के लिए अतिसक्रियता से काम करता रहूंगा जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दी गई उदारवादी लोकतंत्र की उच्च प्रतिबद्धता की परिकल्पना आधारित हो।

उन्होंने अतीत की जिम्मेदारियों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष का आभार प्रकट किया और उनकी अच्छी सेहत की कामना की।

वरिष्ठ वकील कुमार मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार में कानून मंत्री थे। वह 2002 से 2016 तक तीन बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वह अतिरिक्त सॉलीशीटर जनरल भी रह चुके हैं।

कुमार ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को होने वाले मतदान से कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया है।

इससे पहले, गत 25 जनवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था।

अश्विनी कुमार ने अब कांग्रेस छोड़ने वाले उन प्रमुख युवा नेताओं की फेहरिस्त में जुड़ गया है जो कभी कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका में माने जाते थे। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हो गए तो लुईजिन्हो फलेरियो, सुष्मिता देव और अशोक तंवर जैसे कुछ नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया।

संसदीय समिति ने सरकार से कहा : नए वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए 'स्क्रैपेज पॉलिसी' में करें प्रावधान

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एजेंसी)। विभाग संबंधी उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी तीन सौ तेरहवीं रिपोर्ट में सरकार को 'नए वाहनों की खरीद की मांग को बढ़ावा देने के लिए स्क्रैपेज नीति में अग्रिम वित्तीय प्रोत्साहन' के प्रावधान करने का सुझाव दिया है।

तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता और उच्च सदन के सदस्यों डॉ के केशव राव की अध्यक्षता में राज्यसभा के 10 सांसदों और लोकसभा के 21 सांसदों के साथ-साथ संसद सचिवालय के छह सदस्यों वाली समिति ने 'ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी' पर हालिया रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें और टिप्पणियां कीं।

समिति ने भारी उद्योगों से संबंधित पुनरुद्धार का संज्ञान लेते हुए पिछले साल 3 फरवरी को राज्यसभा और लोकसभा के समक्ष पेश समिति की 303वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों और टिप्पणियों पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई पर अपनी 313वीं रिपोर्ट पेश की। भारी उद्योग मंत्रालय ने पिछले वर्ष 22 नवंबर को समिति की 303वीं रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के जवाब पेश किए।

समिति ने प्रारूप-रिपोर्ट पर विचार किया और उसी को अपनाया क्योंकि इसकी बैठक इस साल 3 फरवरी को हुई थी।

समिति ने सिफारिश की, 'समिति का विचार है कि देश भर में ऑटोमोटिव व्हीकल्स स्क्रैपिंग फैसिलिटी केंद्रों की स्थापना के अलावा, सरकार को नए वाहनों की खरीद की मांग को बढ़ावा देने के लिए स्क्रैपेज नीति में अग्रिम वित्तीय प्रोत्साहन के प्रावधान करने चाहिए।'

समिति ने रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहन अंतिम उपयोगकर्ताओं को अपने पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने और नए बीएस-6 अनुपालन वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

इसके अलावा, समिति ने यह भी सिफारिश की कि 'प्रस्तावित एवीएसएफ केंद्र का चयन करते समय पर्याप्त पारदर्शिता बनाए रखी जानी चाहिए, जो पूर्व-निर्धारित मापदंडों के पालन पर आधारित होनी चाहिए जिन्हें ऐसे केंद्रों द्वारा पूरा किया जाना है'।

रिपोर्ट में कार्रवाई की गई उत्तर हेडर में कहा गया है कि, आरवीएसएफ के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) को तैयार करने के लिए पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले साल 15 मार्च को मोटर वाहन (रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शन्स ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी) नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत एक अधिसूचना जारी की थी।

पिछले साल 12 मार्च को जारी मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि सरकारी वाहनों के पंजीकरण का प्रमाण पत्र 15 साल की अवधि के बाद गैर-नवीकरणीय होगा, जबकि पिछले साल 15 मार्च को मसौदा अधिसूचना में पंजीकरण शुल्क, फिटनेस परीक्षण शुल्क और फिटनेस में संशोधन का प्रावधान है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वाहनों का प्रमाण शुल्क और पहल पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में है।

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल 26 मार्च की अधिसूचना के मसौदे में 'वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र' जमा करने पर पंजीकृत वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में रियायत का प्रावधान है। साथ ही, रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल 8 अप्रैल को जारी मसौदा अधिसूचना में 'स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण' का प्रावधान है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सभी पहल 'वाहन स्क्रैपिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने' के लिए हैं।

बाद में, समिति ने सिफारिश की कि ऑटोमोटिव मिशन योजना (2026) का मुख्य उद्देश्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का इंजन बनने के लिए प्रेरित करना है क्योंकि यह विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वालों में से एक है।

इस संबंध में, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए) द्वारा समिति को सूचित किया गया था कि यदि ऑटो क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है, तो यह भारतीय ऑटो डीलरों को, उनके स्वामित्व से बिना समझौता किए, विदेशी निवेश को आकर्षित करके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डीलरशिप समूहों के साथ सहयोग करके विस्तार करने में मदद करेगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि, दुनिया के अन्य देशों की तर्ज पर, एफएडीए ने विशेष रूप से हमारे देश में ऑटो डीलरों के लिए एक फ्रैंचाइजी अधिनियम की जरूरत पर जोर दिया। इसके साथ ही समिति ने कहा कि, एफएडीए द्वारा दिए गए उपरोक्त सुझावों की सिफारिश करता है।

भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने को कहा

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एजेंसी)। रूस व यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन में रह रहे भारतीय अस्थायी रूप से देश छोड़ दें।

यूक्रेन की सीमा पर रूस द्वारा अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाने को लेकर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और मास्को के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने यह कदम उठाया है।

कीव स्थित भारतीय दूतावास ने एक परामर्श में भारत के नागरिकों को यूक्रेन की और यूक्रेन के अंदर सभी गैर-जरूरी यात्रा से बचने को कहा है।

इसमें कहा गया है, यूक्रेन में मौजूदा स्थिति की अनिश्चितताओं के मद्देनजर वहां भारतीय नागरिक, खास तौर पर छात्र, जिनका रहना जरूरी नहीं है, अस्थायी रूप से देश (यूक्रेन) छोड़ने पर विचार कर सकते हैं।

यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की संख्या की जानकारी अभी नहीं है।

हालांकि, 2020 के एक आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक, यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इस आंकड़े में कमी की संभावना है।

यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने परामर्श में भारतीय नागरिकों से अपनी स्थिति के बारे में सूचित करते रहने को कहा है ताकि दूतावास जरूरत पड़ने पर उन तक पहुंच सके।

इसमें कहा गया है कि दूतावास ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को सभी सेवाएं मुहैया करने के लिए सामान्य रूप से कामकाज करना जारी रखा है।

यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ने को लेकर अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने रूस की आलोचना की है।

यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका को मद्देनजर अमेरिका भी अतिरिक्त सैनिकों को यूरोप भेज चुका है ताकि पश्चिमी सहयोगियों को सहयोग दिया जा सके।

रूस ने इस बात से इंकार किया है कि उसकी यूक्रेन पर हमले की कोई योजना है।

सीग्राम का रॉयल स्टैग वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को स्पांसर करता है

सिलीगुड़ी, 15 फरवरी। क्रिकेट हमेशा सीग्राम के रॉयल स्टैग के ब्रांड संचार का केंद्र रहा है। वर्षों से, दुनिया के शीर्ष क्रिकेटरों और टीमों के साथ ब्रांड के निरंतर जुड़ाव ने देश भर के क्रिकेट प्रेमियों के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत किया है। अब, सीग्राम के रॉयल स्टैग ने भारत के मौजूदा दौरे के लिए वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में अपने सहयोग की घोषणा की। टीम वेस्टइंडीज प्रदर्शन का पर्याय है और यह शैली रॉयल स्टैग ब्रांड दर्शन के साथ पूरी तरह से फिट बैठती है- इनाइटस योर लाइफ लिव इट लार्ज। इस जो इसकी अपनी आइकोनिक स्टेटस और 'जेंटलमैन गेम' के लिए प्यारको दर्शाता है, रॉयल स्टैग इन क्रिकेटिंग टाइटन्स के लिए, जड़ें जमाने के लिए तैयार है, जिन्हें पूरे भारत में क्रिकेट प्रेमियों द्वारा पसंद किया जाता है।

पर्नोड रिकार्ड इंडिया के सीएमओ, कार्तिक मोहिंद्रा ने कहा, रॉयल स्टैग लगभग दो दशकों से सीमित ओवरों के क्रिकेट के उत्साह और स्पंदनात्मक कार्रवाई का पर्याय रहा है। 'चल रही सीरीज के लिए वेस्टइंडीज का आधिकारिक प्रायोजक बनकर, हम खेल के जादू के साथ अपना जुड़ाव जारी रखते हैं', उन्होंने कहा।

बाइजु की 'एजुकेशन फॉर ऑल' पहल से 3.4 मिलियन बच्चे प्रभावित हुए हैं

गंगटोक, 15 फरवरी। बाइजु की प्रमुख सामाजिक प्रभाव पहल, एजुकेशन फॉर ऑल (ई एफ ए), अपने लॉन्च के एक साल के माइलस्टोन को चिह्नित करती है और इसने 26 राज्यों और 340+ जिलों में 3.4 मिलियन बच्चों को तकनीक-संचालित शिक्षा को सुलभ, न्यायसंगत और संभव बनाकर प्रभावित किया है। इस महत्वपूर्ण एक वर्ष की उपलब्धि के अवसर पर, बाइजुस एजुकेशन फॉर ऑल ने 2025 तक 5 मिलियन से उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा के माध्यम से 10 मिलियन बच्चों को सशक्त बनाने के अपने लक्ष्यों को संशोधित किया है, जो इस पहल के शुभारंभ पर तय किया गया था।

बाइजुस एजुकेशन फॉर ऑल, अपने सहयोगी गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गियों के बच्चों को बाइजु के मुफ्त स्ट्रीमिंग लाइसेंस तक पहुंच के साथ सीखने का समान अवसर प्राप्त करने मो सक्षम बना रहा है। यह पहल छात्रों को पर्याप्त संसाधनों के साथ सशक्त और सक्षम करके और डिजिटल लर्निंग के व्यापक इकोसिस्टमको बढ़ावा देकर देश भर में डिजिटल विभाजन को खत्म करने के दृष्टिकोण पर केंद्रित है। एजुकेशन फॉर ऑल (ई एफ ए) के वार्षिक माइलस्टोन पर, बाइजुस की को फाउंडर, दिव्या गोकुलनाथ ने कहा, हमारा मानते हैं कि देश के युवा में अपार प्रतिभा है, और सही संसाधनों और समर्थन के साथ, हम एक साथ भारत की भविष्य को बदल सकते हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएगी आयुष चिकित्सा प्रणाली : सर्बानंद सोनोवाल

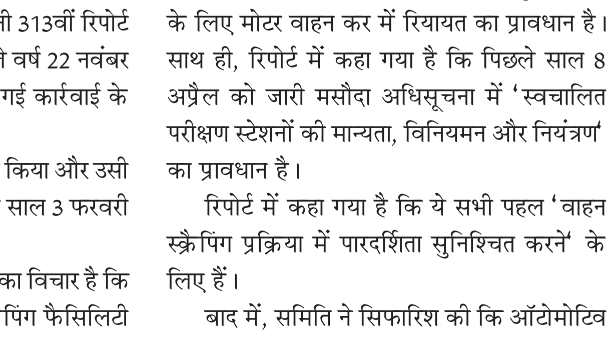

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एजेंसी)। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को कहा कि आने वाले समय में मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा में आयुष व्यवस्था बड़ी भूमिका निभाएगी। सोनोवाल ने कहा कि इलाज की आयुष प्रणाली वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मंत्रालय ने इस प्रणाली को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

असम के पूर्व मुख्यमंत्री सोनोवाल ने कहा कि आयुष मंत्रालय कई देशों के साथ सहयोग से शोध कार्य कर रहा है। हमने अब तक 50 देशों के साथ सहयोगात्मक शोध कार्य विकसित किया है। हम अफ्रीकी देशों में भी प्रयास कर रहे हैं। सोनोवाल ने आगे कहा कि यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें बीमारी से बचाव समेत किसी भी तरह की चुनौती से निपटा जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए यह बहुत अच्छी खबर है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान आयुष उत्पादों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में पारंपरिक दवाओं की जो व्यवस्था है वह सदियों से रही है। आयुर्वेद और योग के उत्पादों और आयुष व्यवस्था ने मानव स्वास्थ्य के संरक्षण में बड़ा योगदान दिया है।

रीबॉक ने पेश किया जिग डायनामिका 3

सिलीगुड़ी, 15 फरवरी। रीबॉक ने अपनी रेट्रो-फ्यूचर जिग फ्रैंचाइजी की अगली पीढ़ी को जिग डायनामिका 3 के लॉन्च के साथ पेश किया है। हाल ही में लॉन्च किया गया जिग डायनामिका 3 रीबॉक के जिग आइकन के तकनीकी शैली और डीएनए के एलिमेंट्स को जोड़कर ऊपरी स्तर पर ध्यान लाता है। कुशनिंग, स्टाइल और वैल्यू का एक आदर्श संयोजन, ये जूते जिग एनर्जी सिस्टम और ऊपरी डिजाइन को एकीकृत करते हैं जो पूरे जूते में गतिशील ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ावा देता है।

सिल्हूट एक विशिष्ट जिगजैग-आकार, एनर्जी-रिटर्न सोल के आसपास बनाया गया है जो एक अत्यधिक कार्यात्मक जूता बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक को फ्यूज करता है जो ऊर्जा प्रवाह के एक आकर्षक और अद्वितीय डिजाइन के निर्बाध रूप से परिणाम देता है। बिल्कुल नया जिग डायनामिका 3 अब आकर्षक रंगों में 7999/- रुपये में shop4reebok.com, चुनिंदा रीबॉक स्टोर्स, और अन्य फैशन रिटेलर्स जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, आजीओ और टाटाक्लिक पर उपलब्ध है।

एरियल ने नया अभियान शुरु किया - #सीइक्वल

सिलीगुड़ी, 15 फरवरी। पिछले 7 वर्षों में, एरियल इंडिया ने घरों के भीतर घरेलू कामों के असमान विभाजन के बारे में लगातार बातचीत की है और अधिक से अधिक पुरुषों से (#शेयरदलोड) काम बराबर बाटनेका आग्रह किया है। इस बातचीत को जारी रखने और घरों में समानता के कारण को आगे बढ़ाने की भावना में, एरियल ने ऽ्सीइक्वल फिल्म लॉन्च की, जिसमें शेयरदलोड के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। एरियल ने एक प्रासंगिक प्रश्न उठाया - 'यदि पुरुष अन्य पुरुषों के साथ समान रूप से कामके भार साझा कर सकते हैं, तो वे अपनी पत्नियों के साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं?'

एरियल पुरुषों से समान भूमिका निभाते हुए समान भागीदार बनने का आग्रह कर रही हैं, क्योंकि जब हम समान देखते हैं, तो हम बराबर भार साझा करते (#शेयरदलोड) करते हैं। इस फिल्म और #शेयरदलोड के 5वें संस्करण को लॉन्च करने के लिए एक रोमांचक पैनल एक साथ आया, जिसमें जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख - अभिनेता, निर्माता, उद्यमी, पर्यावरणविद, अक्षरा सेंटर (एक एनजीओ) से डॉ नंदिता शाह, शरत वर्मा (मुख्य विपणन अधिकारी, पी एंड जी इंडिया, और उपाध्यक्ष, फैब्रिक केयर, पी एंड जी इंडिया), जोसी पॉल (अध्यक्ष और मुख्य रचनात्मक अधिकारी, बीबीडीओ इंडिया) शामिल थे।

पैनल का संचालन शिवानी डांडेकर ने किया। इवेंट में एरियल ने अपना स्पेशल एडिशन एरियल मैटिक पाउडर पैक भी लॉन्च किया। 2015 में #शेयरदलोड अभियान के पहले संस्करण के लिए, एरियल ने एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न उठाया - 'क्या कपड़े धोना केवल एक महिला का काम है?' नवीनतम फिल्म एरियल #शेयरदलोड सीइक्वल जीवनसाथी को समान रूप से देखने के बारे में है क्योंकि जब हम आप समान देखते हैं, तो आप बराबरी का साझा (शेयरदलोड) करते हैं।

दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर किसका होगा नियंत्रण, सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया कि है दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर किसका नियंत्रण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च को याचिका पर सुनवाई शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के अधिकार क्षेत्र को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच जारी विवाद पर तीन मार्च को सुनवाई करेगा।

चीफ जस्टिस एन.वी. रमना और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की डिविजन बेंच ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की अपील स्वीकार करते हुए मामले को 3 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। यह याचिका 2019 के एक खंडित फैसले से उत्पन्न हुई है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच के समक्ष आज विशेष उल्लेख के दौरान दलीलें पेश करते हुए शीघ्र सुनवाई किए जाने की आवश्यकता बताई तथा अगले सोमवार को सुनवाई की अपील की थी।

दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं पर राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के बिना उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण के फैसले को केजरीवाल सरकार ने चुनौती दी है।

इससे पहले विवाद पर 14 फरवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की बेंच ने दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर जीएनसीटीडी और केंद्र सरकार की शक्तियों के सवाल पर एक विभाजित फैसला दिया था और मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया था।

जस्टिस अशोक भूषण ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली सरकार के पास सभी प्रशासनिक सेवाओं का कोई अधिकार नहीं है, जबकि जस्टिस एके सीकरी ने कहा था कि नौकरशाही (संयुक्त निदेशक और ऊपर) के शीर्ष क्षेत्रों में अधिकारियों का स्थानांतरण या पोस्टिंग केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है और अन्य नौकरशाहों से संबंधित मामलों के लिए मतभेद के मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर का विचार मान्य होगा।

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष से संबंधित छह मामलों पर सुनवाई कर रही दो जजों की बेंच ने सेवाओं पर नियंत्रण को छोड़कर शेष पांच मुद्दों पर सर्वसम्मति से आदेश दिया था।

2014 में आम आदमी पार्टी (आप) के सत्ता में आने के बाद से राजधानी दिल्ली के शासन में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता संघर्ष देखा गया है। दिल्ली सरकार का वर्तमान उपराज्यपाल और उनके पूर्ववर्ती के साथ टकराव रहा है।

फरवरी 2019 के फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने 4 जुलाई 2018 को राष्ट्रीय राजधानी के शासन के लिए व्यापक मानदंड निर्धारित किए थे। उस ऐतिहासिक फैसले में बेंच ने सर्वसम्मति से कहा था कि दिल्ली को एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन एलजी की शक्तियों को यह कहते हुए काट दिया था कि उनके पास 'स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति' नहीं है और उन्हें चुनी हुई सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के अधिकार क्षेत्र को भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों तक सीमित कर दिया था और अन्य सभी मामलों में यह माना था कि एलजी को राज्य कैबिनेट की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा।

आशीष मिश्रा आया जेल से बाहर, 128 दिन बाद टेनी के बेटे की रिहाई

लखीमपुर, 15 फरवरी (एजेन्सी)। लखीमपुर के तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मंगलवार की दोपहर जेल से बाहर आ गया। हाईकोर्ट से जमानत के बाद जिला जज की अदालत से उसकी रिहाई का आदेश मंगलवार सुबह जेल पहुंचा। इसके बाद कागजी कार्यवाही पूरी कर आशीष को रिहा कर दिया गया। आशीष 128 दिन बाद जेल से बाहर आया है।

आशीष को मुख्य गेट की जगह पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला गया। इसके पीछे सुरक्षा को कारण बताया गया। इस दौरान मीडिया ने उनसे बात भी करने की कोशिश की लेकिन वह कार में बैठकर निकल गए।

इससे पहले हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद सोमवार को जिला जज की कोर्ट में जमानतनामे दाखिल किए गए थे। जिला जज मुकेश मिश्रा ने दो जमानतदारों और उनके द्वारा जमानत में लगाई गई सम्पत्ति का सत्यापन कराने के लिये संबंधित थानाध्यक्ष और तहसीलदार को आदेश दिया था।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत को संयुक्त किसान मोर्चा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा।

मंगलवार को लखीमपुर में पत्रकारों से बातचीत में टिकैत ने कहा कि किसानों को गाड़ी से कुचलने वाले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सिर्फ तीन महीने में ही जमानत मिल गई। उन्होंने कहा कि तिकुनया हिंसा मामले में केंद्र सरकार ने गृह राज्यमंत्री को उनके पद से भी नहीं हटाया और न ही इस मामले में उनसे पूछताछ हुई।

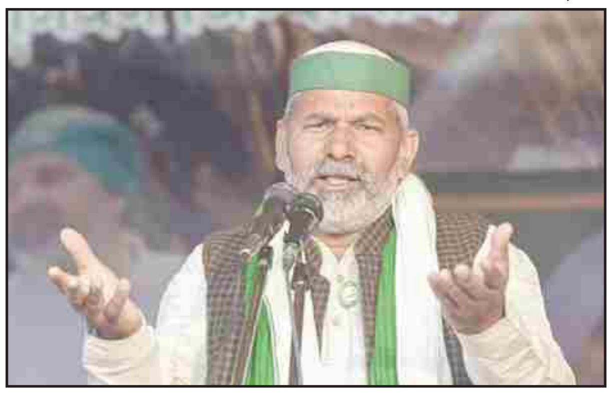

आशीष की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती : टिकैत

तीन अक्तूबर को हुए तिकुनिया कांड में चार किसान, एक पत्रकार, एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ता मारे गए थे। चार किसानों समेत एक पत्रकार की मौत में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू समेत 14 आरोपियों के खिलाफ एसआईटी आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। इसकी सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही है। इस मामले आशीष मिश्र 10 अक्तूबर से जिला जेल में बंद हैं।

जिला जज की अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जमानत के लिए उच्च न्यायालय लखनऊ में अर्जी दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दस फरवरी को जमानत अर्जी मंजूर करते हुए जमानत आदेश जारी कर दिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सोमवार को जिला जज की अदालत में जमानत धनराशि निश्चित करने के लिए अर्जी दी गयी। जिस पर जिला जज ने तीन-तीन लाख रुपये की धनराशि की दो जमानतें और उसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और अंडरटेकिंग दाखिल किए जाने का आदेश दिया।

जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि जिला जज के आदेश के बाद शाम को आशीष के अधिवक्ता द्वारा जमानतनामें कोर्ट में दाखिल कर दिए गए। जिला जज ने जमानतदारों और उनके द्वारा जमानत में लगाई गई सम्पत्ति का सत्यापन कराने के लिए सम्बंधित थानाध्यक्ष और तहसीलदार को आदेशित किया है। जमानतनामे सत्यापित होकर आने के बाद ही कोर्ट से आशीष मिश्र की रिहाई जिला कारागार भेजी जाएगी।

आशीष मिश्र 128 दिनों से जिला जेल में बंद हैं। इस दौरान एक बार तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। एसआईटी के सामने आशीष मिश्र 9 अक्तूबर की सुबह बयान देने के लिये पहुंचे थे। करीब 12 घंटे की गहन पूछताछ के बाद एसआईटी ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया था। रात में ही उन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। एसआईटी ने गहन विवेचना करने के बाद तीन जनवरी को मंत्री पुत्र आशीष समेत 14 आरोपियों के खिलाफ करीब पांच हजार पन्नो की चार्जशीट सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर दी थी।

10 को यूपी में बनवाएं बीजेपी सरकार, 18 को घर आ जाएगा मुफ्त सिलेंडर: अमित शाह

औरैया, 15 फरवरी (एजेन्सी)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रमुख विपक्षी दलों पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ होगा और भाजपा तेजी के साथ 300 सीटों की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा गृहमंत्री ने वादा किया है कि 10 को प्रदेश में बीजेपी की सरकार लाओ और फ्री गैस सिलेंडर पाओ।

अमित शाह ने औरैया के दिबियापुर में आयोजित जनसभा के दौरान कहा कि सपा-बसपा ने उत्तर प्रदेश में 15 साल तक सरकार चलाई, किसी गरीब के घर में गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा। जब जनता ने भाजपा सरकार बनाई मोदी जी ने यूपी की 1.67 लाख माताओं-बहनों को गैस कनेक्शन देने का काम किया। हमने तय किया है कि होली और दीपावली में एक-एक सिलेंडर मुफ्त देने का काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि होली 18 (मार्च) को है और 10 को मतगणना। 10 को प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवांए और 18 तारीख तक आपके घर फ्री गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा। साथ ही किसी भी किसानों को अगले 5 साल तक बिजली का बिल नहीं देना होगा।

अमित शाह ने आगे कहा कि जब कोरोना आया तो पूरी दुनिया में यही चल रहा था कि गरीब क्या खाएगा। लेकिन मोदी जी ने देश के 80 करोड़ और यूपी के 15 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम किया। इसके अलावा मोदी जी ने देश के 130 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों को वैक्सीन न दी होती तो आज हम कोरोना की तीसरी लहर में सुरक्षित नहीं होते। देश की जनता को सुरक्षित करने का काम भाजपा ने किया है।

गृहमंत्री ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी तब यहां कट्टे और छर्रे बनते थे। अब भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में गोली की जगह गोले बनने लगे हैं जो पाकिस्तान को जवाब देने की व्यवस्था की है।

शिवसेना नेताओं को परेशान कर रही हैं केंद्रीय एजेंसियां, बनाया जा रहा है दबाव : संजय राउत

मुंबई, 15 फरवरी (एजेन्सी)। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां हमारी पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही हैं। इन एजेंसियों का इस्तेमाल करने हमारे नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। राउत ने कहा कि कुछ भाजपा नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार 10 मार्च को गिर जाएगी। ये सभी अफवाहें तब से शुरू हुई हैं जब से मैंने वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है।

संजय राउत ने आगे कहा कि ठाकरे परिवार पर अलीबाग में 19 बंगले बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। मैं सभी पत्रकारों को इन बंगलों पर पिकनिक के लिए ले जाऊंगा, अगर वहां पर बंगले नहीं मिले तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना किसी से डरती नहीं है। जो लोग इस समय हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं उनसे साल 2024 के बाद निपटा जाएगा।

राउत ने कहा कि भाजपा के

किरीट सोमैया और उनके बेटे को पीएमसी बैंक घोटाले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। निकॉन इन्फ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी किसकी है? पीएमसी मामले के आरोपी राकेश वाधवान और सोमैया के बेटे इस कंपनी में भागीदार हैं।

शिवसेना नेता ने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार मजबूती से बनी रहेगी। मैंने अमित शाह को फोन किया था और उनसे पूछा था कि क्या मुझसे कोई शत्रुता है। मैंने उनसे कहा कि अगर मुझसे कोई समस्या है तो मुझे गिरफ्तार करिए मेरे मित्रों और परिजनों को परेशान मत करिए। ईडी मेरे घर आ सकती है और मुझे गिरफ्तार कर सकती है।

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े बड़े ठिकानों पर ईडी की मुंबई में छापेमारी

मुंबई, 15 फरवरी (एजेन्सी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े कई ठिकानों पर मुंबई और आसपास के इलाकों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) मामले में छापेमारी की।

दाऊद इब्राहिम की बहन, दिवंगत हसीना पारकर के घर पर ईडी के कुलीन अधिकारियों की एक टीम ने सुबह-सुबह छापा मारा।

सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान उनके पास से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं।

सूत्र ने कहा कि दाऊद इब्राहिम के साथ संबंधों को लेकर महाराष्ट्र का एक राजनेता भी ईडी की नजरों में है।

सूत्र ने कहा, 'हम मुंबई और आसपास के इलाकों में दस स्थानों पर छापेमारी कर रहे हैं। ये गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े पिछले मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित हैं। एक संपत्ति सौदा जांच के दायरे में है, जिसमें महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ राजनेता भी कथित रूप से शामिल हैं।'

ईडी नेताओं और दाऊद के कथित सहयोगियों के पैसे के लेन-देन की भी जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले पर लंबे समय से काम कर रहे थे।

दाऊद अभी भी अपने बिचौलियों के जरिए रियल एस्टेट कारोबार को नियंत्रित कर रहा है। हवाला नेटवर्क के जरिए उसे और उसके सहयोगियों को पैसा भेजा जाता है। इस पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर विभिन्न आतंकी मॉड्यूल द्वारा पूरे भारत में राष्ट्र-विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने के लिए किया जा रहा है। पता चला है कि पाकिस्तान की आईएसआई दाऊद को अपना धंधा चलाने और धंधे से कमाए गए पैसों से आतंकी गतिविधियों को फैलाने में मदद कर रही है।

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 01:00 PM

DEAR TEESTA MORNING

Draw No:64 DrawDate on:15/02/22

1st Prize ₹1 Crore/- 73B 68131

Cons. Prize Rs.1000/- 68131 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-

05469 13957 15127 33033 47188 56463 69115 71113 92757 93284

3rd Prize ₹450/-

0792 2075 2260 2902 3807 5147 8214 8380 9014 9130

4th Prize ₹250/-

1503 2205 2324 3449 4054 5146 5493 6436 7731 7983

5th Prize ₹120/-

0131 0235 0718 0773 0857 0890 0921 0967 0969 1091
1122 1139 1322 1363 1403 1460 1963 1971 2356 2415
2536 2665 2743 2778 2780 2878 2958 3332 3402 3559
3638 3710 3851 3860 4065 4067 4121 4152 4153 4204
4219 4348 4360 4388 4462 4876 4877 5298 5309 5365
5366 5712 5759 5848 6000 6176 6226 6235 6239 6380
6523 6545 6572 6600 6743 6789 6923 6995 7124 7176
7225 7294 7305 7320 7586 7600 7680 7800 7812 7829
7929 7941 8058 8061 8200 8253 8404 8811 8878 8904
9024 9063 9097 9144 9184 9326 9437 9526 9663 9842

ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 08:00 PM

DEAR PARROT EVENING

Draw No:164 DrawDate on:15/02/22

1st Prize ₹1 Crore/- 63D 79372

Cons. Prize Rs.1000/- 79372 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-

17694 20800 25908 33158 36850 50154 50226 57240 70134 88173

3rd Prize ₹450/-

0892 2533 3117 3719 5262 6295 7008 8706 8837 9139

4th Prize ₹250/-

0033 0885 3063 4664 4900 5249 5566 6042 6328 8832

5th Prize ₹120/-

0426 0576 0906 1068 1328 1441 1767 1889 2023 2092
2131 2234 2301 2321 2493 2570 2622 2745 2884 2908
2937 3034 3204 3465 3508 3511 3696 3709 3807 3953
4074 4075 4105 4165 4228 4264 4332 4338 4361 4470
4768 4778 5153 5223 5287 5403 5406 5415 5440 5495
5545 5553 5656 5657 5810 5964 6057 6109 6132 6158
6303 6346 6362 6402 6403 6526 6604 6673 6692 6708
6824 7023 7166 7357 7497 7630 7740 8003 8037 8068
8162 8467 8623 8633 8829 8878 9027 9040 9136 9155
9287 9359 9458 9522 9562 9620 9628 9659 9891 9988

ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 06:00 PM

DEAR MOON TUESDAY

Draw No:64 DrawDate on:15/02/22

1st Prize ₹1 Crore/- 81H 54910

Cons. Prize Rs.1000/- 54910 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-

10905 11237 11667 18140 33636 36368 38285 43532 56166 76409

3rd Prize ₹450/-

1390 1530 2106 3304 5437 7761 7953 8819 9152 9686

4th Prize ₹250/-

1570 2978 3066 3939 4477 4479 5080 6069 7086 8813

5th Prize ₹120/-

0137 0147 0176 0198 0287 0304 0441 0470 0512 0654
0877 1012 1055 1264 1324 1383 1486 1513 1559 1634
1704 2093 2140 2152 2495 2513 2581 2766 2789 2790
2826 2838 2882 3126 3140 3265 3305 3484 3588 4046
4061 4260 4519 4608 4630 4674 5015 5039 5076 5258
5302 5316 5382 5389 5448 5479 5504 5656 5898 5967
6051 6219 6267 6348 6495 6628 6672 6846 6896 6933
6946 6996 7330 7514 7554 7559 7606 7686 7735 7823
7853 7951 8333 8348 8531 8679 8836 8866 8914 8943
9085 9154 9228 9251 9358 9364 9669 9685 9691 9973

ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

SIKKIM STATE LOTTERIES

Draw Time: 08:00 PM

DEAR 100 PARROT TUESDAY

Draw No:5 DrawDate on:15/02/22

1st Prize ₹20LAKHS/- 22440

2nd Prize ₹9000/-

0719 1640 2142 2408 2662 2745 3120 4391 7349 9452

3rd Prize ₹5000/-

0759 2192 2315 2711 3404 3835 5621 6554 7016 9657

4th Prize ₹2000/-

0067 3580 4341 4791 7495 8347 8675 8824 9050 9499

5th Prize ₹1000/-

0598 1067 2204 2341 2509 3091 4301 4761 5310 8774

6th Prize ₹500/-

0070 0131 0135 0308 0331 0391 0441 0736 0938 1017
1094 1123 1143 1179 1206 1336 1340 1345 1349 1431
1457 1583 1666 1729 1785 1966 2209 2300 2411 2641
2647 2691 2917 2985 3071 3076 3156 3234 3338 3369
3390 3552 3656 3684 3915 4066 4072 4242 4273 4283
4339 4392 4429 4519 4596 4614 4621 4724 4729 4911
5038 5366 5379 5487 5492 5671 5729 5741 5886 5917
6076 6555 6649 6729 6797 7015 7065 7073 7130 7576
7583 7681 8098 8239 8272 8288 8297 8306 8358 8536
8590 8833 8844 8909 8911 8925 8958 9115 9308 9400

ISSUED BY : THE DIRECTOR, SIKKIM STATE LOTTERIES,
GOVERNMENT OF SIKKIM DEORALI - 737102, SIKKIM.
For Results, please visit : www.sikkimlotteries.com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

SIKKIM STATE LOTTERIES

Draw Time: 04:00 PM

LABHLAXMI PLATINUM TUESDAY

Draw No:5 DrawDate on:15/02/22

1st Prize ₹10,000/- 5237

2nd Prize ₹5,000/- 4941
3rd Prize ₹500/- 8808
4th Prize ₹300/- 1398
5th Prize ₹200/- 1232
6th Prize ₹100/-

0034 0043 0059 0096 0105 0107 0135 0221 0239 0264
0275 0291 0310 0330 0334 0342 0362 0375 0379 0387
0395 0419 0463 0466 0467 0483 0512 0545 0549 0559
0571 0610 0642 0649 0679 0681 0722 0747 0759 0766
0778 0867 0874 0876 0910 0961 0964 0973 0984 1009
1011 1032 1035 1036 1040 1042 1046 1072 1139 1164
1213 1248 1317 1334 1364 1403 1421 1422 1426 1430
1499 1503 1506 1522 1568 1570 1583 1588 1619 1622
1659 1685 1710 1717 1733 1758 1759 1761 1762 1783
1793 1814 1867 1896 1961 1974 2008 2026 2058 2066
2093 2094 2136 2142 2164 2268 2278 2292 2296 2305
2338 2395 2399 2400 2443 2451 2484 2505 2509 2512
2548 2586 2621 2642 2645 2655 2671 2678 2687 2728
2752 2767 2787 2793 2843 2899 2908 2970 3022 3049
3075 3149 3193 3201 3241 3247 3258 3279 3298 3316
3321 3339 3393 3404 3417 3431 3437 3444 3527 3553
3569 3572 3582 3605 3621 3627 3647 3648 3704 3789
3794 3798 3836 3839 3857 3870 3871 3876 3946 3962
3991 4054 4082 4151 4155 4162 4173 4178 4198 4219
4238 4283 4287 4293 4306 4321 4352 4433 4436 4459
4471 4491 4557 4574 4666 4696 4734 4780 4881 4882
4960 4994 5020 5054 5104 5146 5155 5177 5183 5200
5210 5211 5243 5261 5313 5377 5395 5398 5436 5491
5547 5554 5561 5596 5673 5699 5768 5772 5869 5965
5970 5987 5990 6024 6048 6063 6095 6097 6105 6116
6129 6176 6185 6237 6246 6248 6249 6337 6347 6354
6360 6389 6417 6475 6479 6490 6518 6631 6641 6644
6646 6735 6740 6743 6793 6796 6872 6878 6879 6922
6974 6981 6987 7053 7059 7074 7169 7175 7198 7204
7236 7243 7252 7292 7346 7374 7448 7471 7511 7529
7577 7608 7620 7628 7673 7704 7742 7753 7777 7786
7843 7874 7878 7904 8028 8059 8084 8097 8110 8114
8144 8161 8189 8227 8261 8280 8293 8298 8372 8373
8375 8413 8432 8433 8462 8517 8526 8573 8577 8587
8590 8629 8635 8636 8643 8648 8715 8722 8766 8786
8849 8867 8921 8923 8990 8997 9030 9048 9058 9059
9069 9071 9093 9142 9158 9210 9230 9243 9261 9269
9276 9364 9368 9446 9471 9478 9485 9528 9542 9563
9573 9680 9790 9819 9830 9860 9888 9941 9991 9992

ISSUED BY : THE DIRECTOR, SIKKIM STATE LOTTERIES,
GOVERNMENT OF SIKKIM DEORALI - 737102, SIKKIM.
For Results, please visit : www.sikkimlotteries.com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

SIKKIM STATE LOTTERIES

Draw Time: 07:00 PM

LABHLAXMI TOPAZ TUESDAY

Draw No:5 DrawDate on:15/02/22

1st Prize ₹10,000/- 0680

2nd Prize ₹5,000/- 9480
3rd Prize ₹500/- 5825
4th Prize ₹300/- 9050
5th Prize ₹200/- 1022
6th Prize ₹100/-

0012 0040 0077 0116 0140 0187 0253 0330 0336 0339
0395 0482 0499 0501 0502 0517 0563 0576 0584 0589
0603 0625 0665 0683 0691 0737 0752 0783 0866 0889
0897 0901 0920 0930 1055 1093 1095 1150 1163 1171
1199 1215 1226 1235 1238 1254 1341 1350 1361 1382
1408 1421 1437 1459 1461 1498 1499 1502 1510 1511
1525 1535 1564 1582 1586 1633 1701 1703 1719 1724
1758 1766 1793 1795 1825 1834 1857 1862 1866 1899
1900 1911 1931 1947 1959 1966 1972 2012 2014 2049
2097 2120 2125 2127 2135 2174 2230 2239 2255 2299
2379 2444 2456 2468 2528 2529 2538 2551 2670 2676
2757 2816 2875 2895 2897 2909 3032 3064 3074 3114
3139 3184 3187 3236 3240 3261 3277 3328 3340 3364
3404 3420 3426 3431 3441 3453 3476 3487 3523 3572
3616 3622 3626 3667 3680 3755 3761 3763 3770 3776
3779 3811 3863 3935 3970 4006 4029 4077 4101 4154
4200 4207 4320 4347 4389 4390 4391 4442 4450 4469
4548 4549 4560 4591 4600 4659 4699 4750 4797 4814
4902 4923 4957 5035 5043 5053 5086 5176 5186 5199
5207 5213 5222 5235 5310 5323 5328 5368 5378 5423
5447 5457 5475 5523 5530 5547 5609 5610 5620 5670
5737 5738 5739 5754 5764 5774 5787 5795 5840 5876
5888 5931 5943 5956 5994 6043 6052 6064 6178 6223
6251 6256 6279 6302 6310 6321 6332 6342 6404 6417
6428 6442 6465 6519 6564 6578 6585 6604 6704 6711
6714 6718 6758 6763 6766 6790 6802 6810 6856 6862
6901 6937 6940 6964 7014 7036 7047 7062 7065 7076
7091 7125 7137 7146 7181 7209 7221 7229 7231 7232
7244 7250 7275 7286 7294 7303 7304 7307 7310 7314
7316 7347 7388 7402 7425 7461 7481 7522 7541 7614
7645 7672 7678 7679 7695 7720 7748 7784 7796 7806
7835 7847 7851 7876 7885 7938 7957 8003 8013 8030
8062 8149 8151 8152 8164 8178 8183 8186 8196 8204
8215 8223 8247 8257 8267 8278 8308 8335 8341 8354
8383 8419 8494 8510 8511 8527 8576 8649 8673 8677
8690 8696 8744 8777 8778 8833 8840 8882 8903 8907
8911 8922 8976 9037 9100 9142 9153 9155 9188 9232
9239 9250 9274 9324 9326 9329 9344 9454 9484 9521
9613 9643 9676 9706 9722 9785 9850 9869 9875 9964

ISSUED BY : THE DIRECTOR, SIKKIM STATE LOTTERIES,
GOVERNMENT OF SIKKIM DEORALI - 737102, SIKKIM.
For Results, please visit : www.sikkimlotteries.com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

संपादकीय पृष्ठ

दूसरे दौर का मतदान

कई मायनों में विधानसभा चुनाव का यह चरण सबसे महत्वपूर्ण था। सोमवार को उत्तराखंड और गोवा विधानसभा की सभी सीटों के लिए तो मतदान हुआ ही, साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए दूसरे चरण की 55 सीटों पर भी लोगों ने वोट डाले। उत्तर प्रदेश में अभी मतदान के पांच चरण बाकी हैं, लेकिन उत्तराखंड और गोवा में अगली राज्य सरकारों के लिए लोगों का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। सोमवार को जिन 165 सीटों के लिए मतदान हुआ, वे देश के तीन प्रदेशों में तो बंटी हैं ही, उनका भूगोल भी अलग है, भाषाएं भी अलग हैं और स्थानीय समस्याएं भी। लेकिन कुछ चीजें समान हैं, जो इन तीनों को जोड़ती भी हैं। जैसे, तीनों ही जगह इस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन है, सभी जगह अपनी सत्ता बचाने के लिए उसे एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। कुछ समस्याएं समान हैं, जिन्हें विपक्ष सभी जगह चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। खासकर महंगाई और बेरोजगारी। सरकार से लोगों की नाराजगी का सारा नैरेटिव इन्हीं के आस-पास बुनने की कोशिश हो रही है। इनमें अगर गोवा को छोड़ दें, तो बाकी जगह भाजपा का ग्राफ दो लोकसभा और एक विधानसभा चुनाव, यानी पिछले तीन चुनावों में लगातार ऊपर ही बढ़ा है। इन सभी जगहों पर भाजपा के सामने पुराने आधार को बचाने की चुनौती है, वह भी तब, जब महामारी के लंबे दौर से गुजर चुके देश में बहुत सी चीजें ठीक ढंग से नहीं चल रहीं।

इस लिहाज से देखें, तो उत्तराखंड की लड़ाई सबसे रोचक है। राज्य के मतदाता बारी-बारी से कांग्रेस और भाजपा को सत्ता सौंपते रहे हैं। इस बार भी चुनावी स्पद्र्धा मूल रूप से इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच है। उत्तराखंड देश के उन राज्यों में एक है, जहां बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ, वहां के पर्वतीय क्षेत्रों के गांव बड़े पैमाने पर पलायन की समस्या से भी जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है पर्यावरण में हो रहा बदलाव, जो पूरे प्रदेश के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। बाकी मसलों का तो यदा-कदा जिक्र होता भी है, लेकिन यही एक ऐसा मुद्दा है, जो सभी राजनीतिक दलों की प्राथमिकता सूची से गायब है। गोवा में लड़ाई इस बार बहुकोणीय है। भाजपा, कांग्रेस तो मैदान में हैं ही, आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ इस बार ताल ठोक रही है, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस है, जो पहली बार पश्चिम बंगाल से बाहर बड़े स्तर पर अपना चुनावी भाग्य आजमा रही है। कुछ स्थानीय दल भी हैं। स्पष्ट बहुमत न आ पाने की स्थिति में ये दल हमेशा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पिछली बार यही हुआ था। भाजपा की दिक्कत यह है कि उसके सबसे लोकप्रिय नेता मनोहर पर्रिकर इस बार नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में जिन 55 सीटों के लिए मतदान हुआ है, उनमें से ज्यादातर पिछली बार भाजपा ने जीती थी, लेकिन इस बार उसे नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। प्रदेश का यह वह इलाका है, जहां अल्पसंख्यकों का वोट सबसे महत्वपूर्ण होता है। सोमवार को तीनों राज्यों में हुए चुनाव में अगर हम उत्तर प्रदेश के पिछले चरण के मतदान को भी जोड़ लें, तो इस बार पहले के मुकाबले चुनावी हिंसा की कम घटनाएं रिपोर्ट हुईं। मतदान में गड़बड़ी के आरोप भी कम सुनाई दिए। इससे हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता और चुनाव आयोग के अच्छे प्रबंधन का पता चलता है।

उभरती प्रवृत्ति खतरनाक

अवधेश कुमार

कर्नाटक से आरंभ हिजाब विवाद कई मायनों में डर पैदा करता है। हर व्यक्ति को, वह स्त्री हो या पुरु ष अपना पहनावा चुनने का अधिकार है।

हालांकि मानव सभ्यता का तकाजा यही है कि हम वैसे ही वस्त्र पहन कर लोगों के बीच जाएं जिनसे किसी को अपनी आंखें नीची न करनी पड़े। कहा जा सकता है कि अगर कुछ लड़कियों ने उडुपी के एक कॉलेज में हिजाब पहनकर क्लास रूम में आना शुरू कर ही दिया तो उसे इतना बड़ा वितंडा बनाना गलत है। तर्क दिया जा सकता है कि अगर तूल न दिया जाता तो हिजाब पहनने की जिद अपने आप कुछ दिनों में समाप्त हो जाती।

इन सारे तकरे से आपकी सहमति असहमति हो सकती है, किंतु जरा स्थिति देखिए। कर्नाटक में सभी स्कूल-कॉलेजों के 200 मीटर के दायरे में भीड़ इकट्ठी होने और प्रदर्शन करने पर रोक लगा देनी पड़ी। प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों के नजदीक 22 फरवरी तक धारा 144 लगा दी। दूसरी ओर कर्नाटक उच्च न्यायालय को इसके लिए बड़ी पीठ का गठन करना पड़ा। जो लोग इसे सामान्य घटना या मुद्दा बता रहे थे क्या वे कल्पना कर सकते थे कि मामला उच्च न्यायालय के बड़ी पीठ तक चला जाएगा? विदेशों से इस पर बयान आने लगा है। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री ने हिजाब पहनने वाली छात्राओं का समर्थन कर भारत की आलोचना कर दी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने कह दिया है कि हिजाब में लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना भयावह है।

उन्होंने तो यह भी कहा है कि भारतीय मुसलमानों को हाशिए पर जाने से रोका जाए और उन्हें पढ़ाई से वंचित न रखा जाए। यह सब क्या है? सोशल मीडिया पर ऐसे बयानों की भरमार है, जिसमें लड़कियों को हिजाब पहनकर कक्षा में आने से रोकने को फासीवादी और मानवीय अधिकारों के विरु द्ध साबित किया जा रहा है। इसे धार्मिक आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी के विरुद्ध साबित करने की होड़ लग गई है। एक लड़की मुस्कान, जिसने जय श्री राम नारे के बीच अल्लाह हू अकबर का नारा लगाया वह हीरो बन चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के लिए तो मानो मुंह मांगा विषय मिल गया है। उन्होंने कक्षा में आने पर रोके जाने को संविधान का मखौल भी बता दिया और कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। वास्तव में इसके कई पहलू हैं। यह मामला हिजाब पहनने और न पहनने तक सीमित नहीं है। किसी ने घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं के हिजाब पहनने का विरोध नहीं किया है। यहां मामला एक शिक्षालय का है। तो सबसे पहले इस रूप में देखा जाना चाहिए कि क्या किसी शिक्षालय में अलग-अलग संप्रदायों: मजहबों के छात्र छात्राओं को उनके अनुसार विशेष वस्त्र पहनकर आने की स्वतंत्रता होनी चाहिए? हमारे देश में धार्मिक आस्थाओं के अनुसार लोगों के निर्वस्त्र रहने की भी छूट है। नागा साधु से लेकर दिगंबर संत इसके प्रमाण हैं। जो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को नहीं जानते वे ही आरोप लगाएंगे कि हमारे यहां धर्म के अंदर किसी प्रकार की वांछित स्वतंत्रता पर पाबंदी के प्रावधान हैं।

अगर कोई शिक्षालय अपने यहां छात्र छात्राओं को अपने धर्म या मजहब के अनुसार वस्त्र में आने से रोकता है तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश की बात कहां से आ गई? शिक्षालय को अपना अनुशासन लागू करने का अधिकार होना चाहिए और यह उनकी आजादी के तहत आता है। अगर वे संविधान और कानून के विरु द्ध जाते हैं तो उसका विरोध होना चाहिए। कल्पना करिए इसकी प्रतिक्रिया में दूसरे मजहब-संप्रदायों के सारथी अलग-अलग तकरे के साथ ऐसे ही वस्त्र पहन कर आने लगे तो क्या होगा? किसी वर्ग के अंदर अध्ययन अध्यापन का कैसा माहौल होगा? अगर हम धर्म समागम सहअस्तित्व और सहिष्णुता की बात करते हैं तो उसमें अपने मजहब के नाम पर किसी वस्त्र को लेकर इस तरह की खतरनाक जिद की आवश्यकता क्यों?

यही लड़कियां पहले बिना हिजाब के कक्षा में आती थी और कभी उन्होंने इसकी मांग नहीं की। अचानक उनके अंदर ऐसी भावना कहां से पैदा हो गई इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। जो कुछ सामने आ रहा है, उसमें पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के छात्र विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका दिखाई पड़ रही है। यह संगठन लोगों में कट्टरता फैलाता है। इसके विरुद्ध कार्रवाइयां हुई हैं। इसके लोग अलग-अलग मजहबी अपराध और यहां तक कि आतंकवादी हमलों में भी पकड़े गए हैं। हिजाब के बारे में इस्लाम क्या कहता है इस पर अधिकृत मंतव्य तो उसकी गहरे जानकारी वाले दे सकते हैं।

मामला उच्च न्यायालय से संभव है सर्वोच्च न्यायालय तक जाए। तो संवैधानिक व्याख्या के लिए हमें न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हालांकि हर विषय न्यायालय तय करें यह देश के लिए खतरनाक स्थिति होगी। यह भी तो सोचिए कि उन पांच लड़कियों की ओर से उच्च न्यायालय में जाने वाले कौन लोग होंगे? वह लड़कियां स्वयं तो गई नहीं है। उसी तरह मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने वाले कौन लोग हैं? तो ये कौन लोग हैं, जो एक सामान्य विषय को इतना बड़ा मुद्दा बनाने पर तुले हुए हैं। जाहिर है, इनके इरादे नेक नहीं हैं। इसलिए मुसलमानों के अंदर भी स्वयं को विवेकशील मानने वाले लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा तो चिंता और बढ़ जाती है। उल्टे स्वयं को लिबरल एवं प्रगतिशील मानने वाले लोग हिजाब के समर्थन में आगे आ रहे हैं। प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

विद्यालय में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदस्यों ने प्रदर्शन आरंभ कर दिया। वे हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए थे जिन पर लिखा था हम कर्नाटक की छात्राओं के साथ है। जरा सोचिए, विश्व भर में हजारों मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनतीं। तो क्या वे इस्लाम विरु द्ध आचरण कर रही हैं? हमारे देश में ही लाखों ऐसे लड़कियां हैं जो शिक्षालयों में बिना हिजाब के जाती हैं। क्या यह माना जाएगा कि वह इस्लाम विरुद्ध आचरण कर रही हैं? अगर इस्लाम में हिजाब अनिवार्य होता तो हर लड़की और महिला उसे अपनाने को बाध्य होती। दरअसल, यह प्रचंड तार्किक और प्रभावी विरोध के साथ जागरूकता का मामला है। जब तक समाज का बहुमत इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा ऐसी घातक प्रवृत्तियों पर रोक लगाना कठिन है।

अमेरिकी महंगाई से भारत भी नहीं रहेगा अछूता

अश्विनी महाजन

हालांकि महंगाई भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों में एक आम बात है, पर अमेरिकियों ने कई पीढ़ियों से महंगाई का दंश कभी नहीं झेला। लेकिन पिछले एक साल में अमेरिका में महंगाई की दर लगभग 7.2 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो चालीस साल में सबसे ज्यादा है। महंगाई की ऊंची दर ने सामान्य अमेरिकियों के जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि 2022 के मध्यावधि चुनावों में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

जाहिर है, इसका भारत समेत दुनिया की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ना निश्चित है। कुछ अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कोविड के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा सहायता पैकेज देने के कारण देश में मांग में वृद्धि तो हुई, लेकिन आपूर्ति बाधित होने के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है। बढ़ती महंगाई के कारण मजदूरी दरों में भी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण लागत में वृद्धि महंगाई को और अधिक बढ़ाने का काम कर रही है। अमेरिकी नीति निर्माता इसका ठीकरा आपूर्ति-शृंखला समस्याओं और कच्चे माल की कमी पर फोड़ने को प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्री मुद्रा की बढ़ती आपूर्ति को इसका मुख्य कारण बता रहे हैं। माना जा रहा है कि महंगाई से जल्द ही कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

अमेरिका में कई नीति निर्माताओं का कहना है कि कीमत नियंत्रण से महंगाई को रोका जा सकता है। लेकिन इसका एक नुकसान यह होता है कि उत्पादकों का अधिक उत्पादन हेतु प्रोत्साहन कम हो जाता है। आशंका यह है कि इसके कारण उपभोक्ताओं को वस्तुओं की कमी से जूझना पड़ सकता है। अमेरिका के नीति निर्माता अपनी पूर्व की गलती पर पर्दा डालने के लिए तरह-तरह के तर्क दे रहे हैं, और वह गलती है मुद्रा का जरूरत से ज्यादा विस्तार। इतिहास गवाह है कि महंगाई का मुख्य कारण मुद्रा का विस्तार ही होता है।

अमेरिकी नीति निर्माता भी मानते हैं कि अमेरिका में लोगों के पास भारी बचत शेष है और कोविड के दौरान जो वस्तुएं या सुविधाएं वे नहीं खरीद पाए, उसकी अब भरपाई करना चाहते हैं। लेकिन समझना होगा कि लोगों के पास बचत का असली कारण सरकार द्वारा भारी मात्रा में आर्थिक सहायताओं का वितरण है।

कोविड संकट के दौरान सीमित आमदनी के कारण सरकार द्वारा करेंसी की मात्रा में वृद्धि की गई, जिसके कारण मुद्रा प्रवाह में बड़ी वृद्धि से महंगाई में वृद्धि अवश्यंभावी हो गई है। अमेरिकी सरकार द्वारा अतिरिक्त मुद्रा का सृजन करते हुए सरकारी सहायताएं देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से डॉलर की वैश्विक लोकप्रियता में कुछ कमी आई है, जिसका स्थान चीन की मुद्रा युआन ले रहा है। ऐसे में अमेरिका के बाहर डॉलर की आपूर्ति कम हो रही है। लगता है कि भविष्य में यदि युआन के प्रति आकर्षण की यह प्रवृत्ति जारी रही, तो अमेरिका में बढ़ती मुद्रा की आपूर्ति भविष्य में भी महंगाई का कारण बनती रहेगी। जहां तक अमेरिका की बढ़ती महंगाई का भारत पर असर पड़ने की बात है, तो भारत और भारतीय जो कुछ भी अमेरिका से आयात करते हैं, वह सब कुछ महंगा हो जाएगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ने से आयातित मुद्रास्फीति ज्यादा होती है। अमेरिका की उच्च मुद्रास्फीति उसके केंद्रीय बैंक को नरम मौद्रिक नीति को त्यागने के लिए बाध्य करेगी, जिससे वहां ब्याज दर बढ़ेगी।

यह भारतीय अर्थव्यवस्था को दो तरीके से प्रभावित करेगा। एक तो, जो भारतीय कंपनियां देश से बाहर पैसा जुटाने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए ऐसा करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी निवेशक अमेरिका में ही निवेश करना चाहेंगे।

दूसरे, रिजर्व बैंक को घरेलू स्तर पर अपनी ब्याज दरें बढ़ाकर अपनी मौद्रिक नीति में तालमेल बिठाना होगा। बदले में इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, क्योंकि उत्पादन लागत बढ़ जाएगी।

पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी

मोनिका शर्मा

देश का कोई भी हिस्सा हो, महिलाओं के लिए सशक्त और सहज जीवन जीने की स्थितियां, उनकी सुरक्षा से जुड़ा सबसे प्रमुख पहलू है। साथ ही भयरहित परिवेश से संबंधित अधिकतर चीजें पुलिस बल से जुड़ी हैं। सुरक्षित महसूस करने से लेकर शिकायत करने और जांच के दौरान संवेदनशील व्यवहार से जुड़ी अनगिनत बातें या तो पुलिस बल में भरोसा बढ़ाती हैं या असुरक्षित महसूस करवाती हैं।

ऐसे में हाल ही में उठाए गए एक कदम की ओर ध्यान जाता है। पुलिस-प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और सुधार के लिए बनी संसद की स्थायी समिति ने पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी तैंतीस फीसदी करने की सिफारिश की है। पुलिस बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना मानवीय संवेदनाओं से जुड़े मोर्चों पर प्रभावी बदलाव ला सकता है।

समिति ने यह भी सुझाया है कि सिर्फ पुरुषों के खाली पदों को महिलाओं से भरने का काम ही नहीं किया जाए, बल्कि महिलाओं के लिए अलग से नए पद भी सृजित किए जाएं। गौरतलब है कि अभी पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या 10.30 फीसदी ही है। जबकि देश की आबादी का 48 प्रतिशत हिस्सा महिलाएं हैं। यही नहीं, घर हो या बाहर अधिकतर आपराधिक घटनाएं भी महिलाओं के साथ ही होती हैं। यही वजह है कि लंबे समय से पुलिस में महिलाओं को कम से कम एक तिहाई हिस्सेदारी दिए जाने की बात हो रही है।

पुलिस बलों में महिलाओं का सीमित प्रतिनिधित्व यकीनन चिंता का विषय है। पुलिस बलों में महिलाओं की भागीदारी का कम होना देश की आम स्त्रियों के मन-जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाला पक्ष है। उनकी सुरक्षा और सहजता पर असर डालने वाला मामला है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि देश में 11 फीसदी अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं। कई घटनाओं में महिला अपराधियों की भी गिरफ्तारी की जाती है। कहना गलत नहीं होगा कि बच्चों से जुड़े मामले भी महिला पुलिसकर्मियों को सौंपे जाएं, तो बेहतर ढंग से हल किए जा सकते हैं।

रिपोर्ट में हर थाने में तीन महिला सब-इंस्पेक्टर के अलावा 10 महिला कांस्टेबल की तैनाती के साथ ही हर जिले में महिला थाना बनाने की बात भी कही गई है। संसदीय समिति के सुझाव वाकई गौर करने लायक हैं, क्योंकि हमारी सामाजिक-पारिवारिक रूपरेखा और इंसानी व्यवहार को समझने वाले विशेषज्ञ भी पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कहते रहे हैं। उनका भी मानना है कि पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर इसे और ज्यादा मानवीय बनाया जा सकता है। समाजशास्त्री तो यह भी कहते हैं कि कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में भी स्त्रियों की भागीदारी बढ़ाना सीधे-सीधे काम की कुशलता और शिकायतकर्ताओं की सहजता से जुड़ा पक्ष है।

सुखद यह है कि इस मोर्चे पर कोशिशें जारी हैं। साल की शुरुआत में ही जम्मू-कश्मीर पुलिस में महिलाओं के लिए 15 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

राज्य पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने का यह प्रयास जरूरी भी था, क्योंकि राज्य में केवल तीन फीसदी महिलाएं ही पुलिस बल में हैं। समिति ने इस ताजा रिपोर्ट में भी कहा है कि राज्य पुलिस बलों में 26,23,225 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 5,31,737 रिक्तियां ही भरी गई हैं।

बीते साल आई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2020 के मुताबिक, बिहार में दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं। राज्य के पुलिस बल में 25.3 फीसदी महिलाएं हैं।

इसी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर दस पुलिसकर्मियों में मात्र एक महिलाकर्मी है। समझना जरूरी है कि पुलिस फोर्स में महिलाओं की भागीदारी केवल आधी आबादी के रोजगार पाने या किसी एक क्षेत्र विशेष में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने भर की बात नहीं है। स्त्रियों की यह हिस्सेदारी महिला सुरक्षा का पूरा परिदृश्य बदलने वाली बात है।

जोश जगाता है तारापुर आजादी संग्राम

जयराम विप्लव

भारतवर्ष के गौरवशाली अतीत का स्वर्णिम अध्याय लिखने वाले तारापुर के बलिदानी वीर हमारी स्मृतियों में जीवित है वो मर नहीं सकते।

गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है न जायते म्रियते वा कदाचि न्नायं भूत्वा भविता वा न भूय:। अजो नित्य: शाश्वत्यो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

तारापुर के बलिदानियों के राष्ट्र प्रेम के तत्व ने कालचक्र की सीमाओं के पार जाकर उन्हें अमर कर दिया। और आज जब भारत आजादी के 75 वें वर्ष का समारोह अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत काल में इतिहास में अछूते रह गए उन राष्ट्र नायकों की जीवनी, उनसे जुड़ी जगहों और घटनाओं को प्रकाश में लाने का भागीरथी प्रयास हो रहा है, जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। इसी कड़ी में 31 जनवरी 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी ने इतिहास के एक और अछूते अध्याय का जिक्र किया तो देश भर में तारापुर शहीद दिवस का इतिहास खोजा जाने लगा है। 15 फरवरी 1932 का वो बलिदानी दिन तारापुर ही नहीं समूचे भारतवर्ष के लिए गौरव का दिन है जब क्रांतिकारियों के धावक दल ने थाना पर तिरंगा फहराते हुए जान की बाजी लगा दी थी। तारापुर ब्रिटिश थाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के क्रम में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का दूसरा सबसे बड़ा गोलीकांड आज 90 वर्ष पूरे कर रहा है, जब 34 सपूतों ने बलिदान दिया था।

पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता की जनआकांक्षा के अंकुर ने कालांतर में आकार लेना प्रारंभ कर दिया था। सन 57 में बाबू वीर कुंवर सिंह के अस्सी वर्षो की हड्डी में जागे जोश ने जब अंग्रेजी झंडे को जगदीशपुर से उखाड़ फेंका तो मानो बिहार की तरुनाई आजादी की अंगड़ाई लेने लगी। समय बीतता गया और मातृभूमि की स्वतंत्रता की यह लड़ाई गांव-कस्बों तक पहुंचने लगी थी, सन 32 का तारापुर गोलीकांड और सन 42 में जनता सरकार की स्थापना इसका जीवंत उदाहरण है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अलग-अलग कालखंड में बिहार के राष्ट्रभक्तों ने अपने साहसिक और बलिदानी प्रयासों से अपनी अमिट छाप छोड़ी है। वक्त के साथ मुंगेर-भागलपुर सहित अंग क्षेत्र बिहार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया था। मातृभूमि की रक्षा के लिए जान लेने वाले और जान देने वाले दोनों तरह के सेनानियों ने अंग्रेज सरकार की नाक में दम कर रखा था। स्वतंत्रता आंदोलन में तारापुर की बात करें तो, तारापुर का हिमालय ढोल पहाड़ी इंडियन लिबरेशन आर्मी का शिविर था, जिसका संचालन क्रांतिकारी बिरेन्द्र सिंह करते थे। इनके प्रमुख सहायक डॉ. भुवनेर सिंह थे। यहां के शिविर में दर्जनों ऐसे क्रांतिकारी थे जो अपने क्रांतिकारी नेता के एक इशारे पर देश की आजादी के लिए जान हथेली पर लेकर घूमते थे। स्वतंत्रता के सिपाहियों का दूसरा बड़ा केंद्र संग्रामपुर प्रखंड के सुपौर जमुआ ग्राम स्थित श्रीभवन से संचालित होता था, जहां उस वक्त कांग्रेस से बड़े-बड़े नेता भी आया करते थे। इसी केंद्र से तारापुर तरंग और विख्रलव जैसी क्रांतिकारी पत्रिका छपती थी। तारापुर में भी स्वतंत्रता के लिए नरम दल और गरम दल दोनों तरह के सेनानी सक्रिय थे। उन दिनों बिहार के अंग क्षेत्र में मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय सहित कोसी के इलाकों तक जनमानस अनेक छोटी-छोटी घटनाओं से सुलग रहा था। इसी दौरान 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी ने पूरे देश के युवाओं में उबाल ला दिया। आजादी का विचार आग की तरह गांव-कस्बों तक पहुंचने लगा था। उधर 1931 में गांधी-इरविन समझौता भंग हो चूका था और 27 दिसम्बर 1931 को गोलमेज सम्मेलन लंदन से लौटते ही 1 जनवरी 1932 को जब महात्मा गांधी ने पुन: सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर सभी कांग्रेस कार्यालय पर भारत का झंडा (तत्कालीन कांग्रेस का झंडा) उतार कर ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक लहरा दिया।

4 जनवरी को गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे। सरदार पटेल, जवाहर लाल नेहरू और राजेंद्र बाबू जैसे दिग्गज नेताओं सहित हर प्रांत के प्रमुख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी हुकूमत इस दमनात्मक कार्रवाई और भारत पर उनकी नाजायज हुकूमत के खिलाफ देशभर में एक आक्रोश पनपने लगा था। लार्ड विलिंग्डन के उस ऐतिहासिक दमन से मुंगेर भी अछूता नहीं रह पाया था। श्रीकृष्ण सिंह, नेमधारी सिंह, निरापद मुखर्जी, पंडित दशरथ झा, बासुकीनाथ राय, दीनानाथ सहाय, जय मंगल शास्त्री आदि गिरफ्तार हो चुके थे। ऐसे में युद्धक समिति के प्रधान सरदार शार्दुल सिंह कवीर द्वारा जारी संकल्प पत्र कांग्रेसियों और क्रांतिकारियों में आजादी का उन्माद पैदा कर गया और इसकी स्पष्ट गूंज 15 फरवरी 1932 को तारापुर के जरिये लंदन ने भी सुनी। सरदार शार्दुल सिंह के द्वारा प्रेषित संकल्प पत्र में स्पष्ट आह्वान था कि सभी सरकारी भवनों पर तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाए। उनका निर्देश था कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में पांच ध्वजवाहकों का जत्था राष्ट्रीय झंडा लेकर अंग्रेज सरकार के भवनों पर धावा बोलेगा और शेष कार्यकर्ता 200 गज की दूरी पर खड़े होकर सत्याग्रहियों का मनोबल बढ़ाएंगे।

जिस तरीके से कोविड-19 ने विश्व भर में विस्तार पाया है, कम से कम उस स्तर पर किसी बीमारी का तीव्र विस्तार ना हो सके। जाहिर तौर पर इस स्थिति को पहचानने और महामारी के भिन्न लक्षणों का स्तर, कोई एपिडेमियोलॉजिस्ट ही समझ सकता है।

पैनडेमिक सिचुएशन से उबारने के बनें विशेषज्ञ

कोविड-19 ने जिस प्रकार से समूची दुनिया को हिला कर रख दिया है। इससे लोग एक बार फिर सोचने को मजबूर हो गए हैं कि क्या हमारे पास महामारी से संबंधित ढेर सारे विशेषज्ञ होने चाहिए, जो ऐसी स्थिति आने पर अपने ज्ञान और अपने जज्बे से हमें इस मुसीबत में फंसने से बचा लें। खुदा न खास्ता अगर मुसीबत में कोई फँस भी जाता है, तो जिस तरीके से कोविड-19 ने विश्व भर में विस्तार पाया है, कम से कम उस स्तर पर किसी बीमारी का तीव्र विस्तार ना हो सके। जाहिर तौर पर इस स्थिति को पहचानने और महामारी के भिन्न लक्षणों का स्तर, कोई एपिडेमियोलॉजिस्ट ही समझ सकता है। ऐसे में आपके सामने एपिडेमियोलॉजिस्ट बनने हेतु कॅरियर में अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आइये जानते हैं.

वास्तव में देखें तो दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ''पहला सुख, निरोगी काया''। कल्पना कीजिए कि किस स्तर का डर फैल जाता है, अगर स्वास्थ्य पर संकट आ जाए। बात और भी गंभीर हो जाती है अगर कोई एक बीमारी समूचे विश्व पर एक महामारी की शक्ल में आये। ऐसे में कुछ भी कहना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि तब स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसी किसी बीमारी की रोकथाम के फुलप्रूफ इंतजाम होने चाहिए। ऐसे में एपिडेमियोलॉजिस्ट का प्रोफाइल यहां बेहद कामयाब दिखता है। इसमें किसी बीमारी की पहचान और वह कितनी तेजी से फैल सकती है और उसे प्रभावी ढंग से कैसे रोक सकते हैं, यह कार्य अपने रिसर्च के द्वारा एक एपिडेमियोलॉजिस्ट ही कर सकता है। एपिडेमियोलॉजिस्ट में मुख्यत: दो भाग हैं, जिसमें एक रिसर्च फील्ड से संबंधित है तो दूसरा क्लीनिकल फील्ड से संबंधित है।

वस्तुत: यह पूरी तरह से प्रोफेशनल होते हैं जो महामारी जैसे रोगों में लोगों की प्रतिक्रिया से लेकर, जेनेटिक बीमारी और बायो टेररिज्म तक पर कार्य करते हैं। इसके लिए आपके पास एक मास्टर डिग्री होना चाहिए। हमारे देश की बात करें तो इसके लिए 12वीं पास स्टूडेंट, जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ली हुई है। वह बीएससी अथवा दूसरे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अपना दाखिला करा सकता है और ऐसे ही जब आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो यह जान लें कि किसी भी यूनिवर्सिटी से कम से कम 55 फीसदी मार्क आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके पश्चात एपिडेमियोलॉजिस्ट के संबंध में प्रचलित तमाम कोर्सेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें बैचलर आफ साइंस, पब्लिक हेल्थ में बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। इसके बाद मास्टर ऑफ साइंस एपिडेमियोलॉजिस्ट में आता है। तत्पश्चात पीजी डिप्लोमा और अंत में आप एपिडेमियोलॉजिस्ट से पीएचडी कर सकते हैं। अथवा पब्लिक हेल्थ से पीएचडी कर सकते हैं।

स्कूल की बात करें तो दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू, मुंबई स्थित होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद है। ऐसे ही चेन्नई में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एपिडेमियोलॉजी स्थापित है। इसके अलावा आईआईटी के विभिन्न संस्थान इसकी ट्रेनिंग देते हैं। जैसे आईआईटी गांधीनगर, टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज मुंबई, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, तमिलनाडु, राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, पटना, जिसके नाम से भी जाना जाता है।

टीचर, ग्रुप स्टडी और दोस्तों के साथ पढ़ाई से आप एक तरह से वंचित हो चुके हैं, इसलिए समय प्रबंधन आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। अब टाइम टेबल के अनुसार विषय वाइज पढ़ाई कीजिए और इससे निश्चित रूप से परीक्षा हाल में आपको बेहतर परिणाम दिखेगा।

कोरोना के दौर में बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए टिप्स

कोरोना महामारी ने जिन सेक्टर्स को सर्वाधिक डिस्टर्ब किया है, उनमें से एजुकेशन सेक्टर प्रमुख है। अगर यह कहा जाए कि पूरे साल को कोविड-19 ने, एजुकेशन के लिहाज से बर्बाद कर दिया, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से कुछ स्कूल और दूसरी शैक्षणिक संस्थाएं बच्चों को पढ़ाने की कोशिश जरूर करती दिखीं, परंतु स्कूलों में होने वाली पढ़ाई और वहां मिलने वाला पढ़ाई का माहौल, अगर घर पर ही मिल जाए, तो फिर स्कूल की जरूरत ही क्यों पड़े? परंतु हकीकत यह है कि बावजूद तमाम मुसीबतों के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि सीबीएसई द्वारा घोषित हो चुकी है। 4 मई से 10 जून तक यह परीक्षाएं चलेंगी और इसका परिणाम जुलाई में घोषित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने तैयारी कर ली है। कमोबेश इसी से मिलते जुलते डेट्स तमाम राज्यों के बोर्ड भी जल्द ही घोषित कर देंगे।

ऐसे में बच्चों के सर पर एग्जाम का बोझ तो आ ही गया, बेशक उनकी पढ़ाई हुई हो या नहीं! मतलब परीक्षाएं होंगी। हालांकि इसके लिए अभी समय जरूर है, पर अगर आज से ही सजगता नहीं बरती गई, तो इसके परिणाम बहुत बेहतर नहीं आएंगे और इस बात का यकीन जितनी जल्दी से जल्दी कर लिया जाए, तो बेहतर रहेगा!

टाइम टेबल

जी हां! कहते हैं कि संसार में एक समय ही ऐसी चीज है, जो कभी रुकता नहीं है! अगर आपने बीआर चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत के एपिसोड देखे हैं, तो उसमें ''मैं समय हूं'' का मशहूर संवाद अवश्य ही सुना होगा। सच तो यह है कि अगर आप समय की कीमत नहीं समझते हैं, तो सामान्य दिनों में भी आप बहुत अच्छा परिणाम नहीं ला सकते हैं, और हाल फिलहाल तो कोरोना वायरस आपका आधा समय यूं ही निकाल चुका है। टीचर, ग्रुप स्टडी और दोस्तों के साथ पढ़ाई से आप एक तरह से वंचित हो चुके हैं, इसलिए समय प्रबंधन आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। अब टाइम टेबल के अनुसार विषय वाइज पढ़ाई कीजिए और इससे निश्चित रूप से परीक्षा हाल में आपको बेहतर परिणाम दिखेगा।

हेल्थ के बिना कुछ भी ठीक नहीं!

स्कूल जाने पर आप ना चाहते हुए भी काफी कुछ पढ़ लेते थे, शारीरिक भाग दौड़ भी हो ही जाती थी, किंतु लॉकडाउन में और उसके बाद स्कूल नहीं खुलने से आप कहीं आलसी तो नहीं हो गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी हेल्थ के प्रति लापरवाह हो गए हैं? खैर, अब सजग हो जाइए! सुबह जगने से लेकर, नाश्ता, पौष्टिक भोजन और शाम को थोड़ा बहुत टहलने से लेकर, सही समय पर सोना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और हां! सुबह सुबह व्यायाम करने से आपका पूरा दिन तरोताजा रहता है और इससे आप तो बेहतर स्टडी अवश्य कर सकते हैं। एक बार पुन: इस बात को दोहरा लीजिए कि बगैर उत्तम हेल्थ के आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा और किताब खोल कर बेशक आप बैठे रहें, परंतु आपको, आप ही के मन मस्तिष्क द्वारा बेहतर परिणाम नहीं प्राप्त होगा।

पूछिये, ढूँढिये, किंतु भटकिये नहीं!

लॉकडाउन में आप इंटरनेट की मदद लेना तो सीख ही गए होंगे, किंतु इंटरनेट पर कितना भटकाव है, यह भी आप महसूस अवश्य कर चुके होंगे। पहले आपने सोशल मीडिया इत्यादि पर समय नुकसान किया ही होगा, तमाम गैर जरूरी वीडियोज देखा होगा, दोस्तों के साथ गेम और चैट में समय खराब किया होगा, पर अब यह ना करिए! आप इंटरनेट की मदद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जरूर कीजिए, किंतु समय नुकसान ना हो, उस पर भटकिए नहीं! इंटरनेट जहां फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहीं यह आपका समय कितनी जल्दी व्यतीत कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बेहद सजगता के साथ ही इंटरनेट ब्राउजिंग करें और अपने घड़ी की सुईयां देखते रहें। साथ ही इंटरनेट के अलावा भी आप अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें तनिक भी हिचकिचाहट पालने की जरूरत नहीं है।

शांत वातावरण में रिवीजन

जिस प्रकार से जिम में एक बॉडीबिल्डर रोज एक ही व्यायाम का अभ्यास करता है, ठीक उसी प्रकार आपको अपने सब्जेक्ट का लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, उसका रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस, जल्द ही कन्फ्यूजन में बदल जाएगा। वहीं इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। अगर आप किसी टॉपिक को लेकर कन्फ्यूजन में हैं, तो रिवीजन करने से निश्चित रूप से आपको कॉन्फिडेंस प्राप्त हो जाएगा। हालांकि इसके लिए कोशिश करें कि आपको थोड़ा पीसफुल एनवायरमेंट मिले। टेलीविजन, इंटरनेट और दूसरे म्यूजिक इत्यादि माध्यमों से दूर रहकर एकांत में रिवीजन करने से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं, इस बात में दो राय नहीं है।

सीखिए लैपटॉप रिपेयरिंग और बनाएं उज्ज्वल भविष्य

लैपटॉप रिपेयरिंग के क्षेत्र में कॅरियर देख रहे छात्रों के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता का होना जरूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से दसवीं व बारहवीं के बाद लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं। आप इस क्षेत्र में शार्ट टर्म कोर्स से लेकर सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं।

इस बात में कोई शक नहीं नहीं है कि लैपटॉप आज के समय में हमारे दैनिक जीवन की एक आवश्यकता बन गया है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बैंकिंग व ऑफिस के काम आदि निपटाने के लिए हर व्यक्ति लैपटॉप को प्राथमिकता देता है। कुछ समय पहले तक जहां डेस्कटॉप का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इनसे ज्यादा लैपटॉप को तवज्जो मिलने लगी है, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल करना अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक है। ऐसे में लैपटॉप रिपेयरिंग के क्षेत्र में भी कॅरियर की नई संभावनाएं पैदा हुई है। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं लैपटॉप रिपेयरिंग के क्षेत्र में कॅरियर-

स्किल्स- कॅरियर एक्सपर्ट के अनुसार, लैपटॉप रिपेयरिंग के क्षेत्र में कॅरियर देख रहे छात्रों के भीतर सीखने की गहन इच्छा होनी चाहिए। इसके अलावा आपको लैपटॉप हार्डवेयर की भी अगर थोड़ी-बहुत जानकारी होगी तो यह आपके लिए अच्छा होगा। इस क्षेत्र में छात्रों में मार्केट में लॉन्च हो रहे नए लैपटॉप व उनकी क्वालिटीज के बारे पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के अपडेट होने के साथ-साथ अगर आप भी खुद को अपग्रेड रखते हैं तो इससे आपको अतिरिक्त लाभ होगा।

कोर्स- लैपटॉप रिपेयरिंग के क्षेत्र में कॅरियर देख रहे छात्रों के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता का होना जरूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से दसवीं व बारहवीं के बाद लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं। आप इस क्षेत्र में शार्ट टर्म कोर्स से लेकर सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इनकी अवधि तीन से छह माह तक हो सकती हैं।

संभावनाएं- कॅरियर एक्सपर्ट बताते हैं कि लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करने के बाद आपके पास काम की कोई कमी नहीं होती। दरअसल, आज के समय में लैपटॉप हर व्यक्ति की जरूरत बन गया है और इसलिए उसकी रिपेयरिंग के लिए एक्सपर्ट की डिमांड भी बढ़ी है। कोर्स करने के बाद आप लैपटॉप व कंप्यूटर रिपेयर शॉप्स, लैपटॉप सेल्स सेंटर, लैपटॉप शोरूम, लैपटॉप सर्विस सेंटर आदि में काम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ समय के अनुभव के बाद आप खुद की लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप भी खोल सकते हैं।

आमदनी- इस क्षेत्र में आमदनी मुख्यत: आपके अनुभव और स्किल्स के आधार पर तय होती है। कोर्स करने के बाद आप शुरूआती दौर में 15000 से 20000 रूपए महीना सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समय के अनुभव के बाद आपकी सैलरी में इजाफा होता है। इतना ही नहीं, अगर आप खुद की लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप खोलते हैं तो आपकी मासिक आमदनी हजारों से लेकर लाखों में हो सकती है।

पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब छात्र अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखते हैं तो उनकी जिन्दगी काफी बदल जाती है। कॉलेज की मौज-मस्ती के बाद उन्हें अपने कॅरियर को लेकर काफी सजग होना पड़ता है, ताकि वह अपना बेहतर भविष्य बना सके। कॅरियर में ग्रोथ के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप बार-बार अपनी जॉब या कंपनी बदलें, बल्कि आपकी पहली जॉब ही आपको नई ऊचांइयों पर ले जा सकती है, बस जरूरत है कि आप कुछ बातों का खास ध्यान दें। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको फ्रेशर्स के लिए कुछ बेहतरीन कॅरियर टिप्स के बारे में बता रहे हैं-

अधिकतर कंपनियां ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहती हैं जो टीम में बेहद अच्छी तरह काम करना जानते हों। ऐसे में अगर आप फ्रेशर हैं और अपने कॅरियर को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको टीम में काम करना आना चाहिए।

फ्रेशर्स के लिए कॅरियर टिप्स

टीम में काम करना

कॅरियर एक्सपर्ट बताते हैं कि अधिकतर कंपनियां ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहती हैं जो टीम में बेहद अच्छी तरह काम करना जानते हों। ऐसे में अगर आप फ्रेशर हैं और अपने कॅरियर को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको टीम में काम करना आना चाहिए। आपको ऑफिस में कई पर्सनैलिटीज के लोग मिलेंगे, जिनके साथ आपको सहज रूप से काम करना चाहिए। साथ ही किसी भी जिम्मेदारी को उठाना आना चाहिए।

दबाव में काम करना

यह एक ऐसा स्किल है, जो फ्रेशर्स के अंदर कम ही देखने में मिलता है। हालांकि कॅरियर एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप प्रेशर के बीच बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं तो यकीनन अपने कॅरियर में तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। अत्यधिक काम के दबाव में खुद को शांत रखते हुए सही तरीके से काम करने की कला किसी भी कंपनी में उच्चाधिकारियों को इंप्रेस कर सकती हैं।

बेहतर कम्युनिकेशन

यह एक ऐसा कॅरियर टिप्स है, जो सिर्फ फ्रेशर्स के लिए ही नहीं, बल्कि हर युवा के लिए जरूरी है। आप अपने काम में चाहें कितना भी माहिर हों, लेकिन अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं है तो आप उसे सबके साथ पेश नहीं कर सकते, जिससे आपको अपने कॅरियर में ग्रोथ नहीं मिलती। इसलिए अपने वर्क स्किल्स के साथ-साथ आपको मौखिक व लिखित कम्युनिकेशन स्किल्स को शॉर्प करने पर भी फोकस करना चाहिए।

अन्य स्किल्स

इनके अलावा भी ऐसी कई बाते हैं जो आपके कॅरियर को प्रभावित कर सकती है। मसलन, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप अपने काम को लेकर कितना फलेक्सिबल हैं या फिर आप अपने वाडरोब पर कितना ध्यान देते हैं। जैसी कई छोटी-छोटी बातें आपके कॅरियर को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। इसलिए इन सभी बातों पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए।

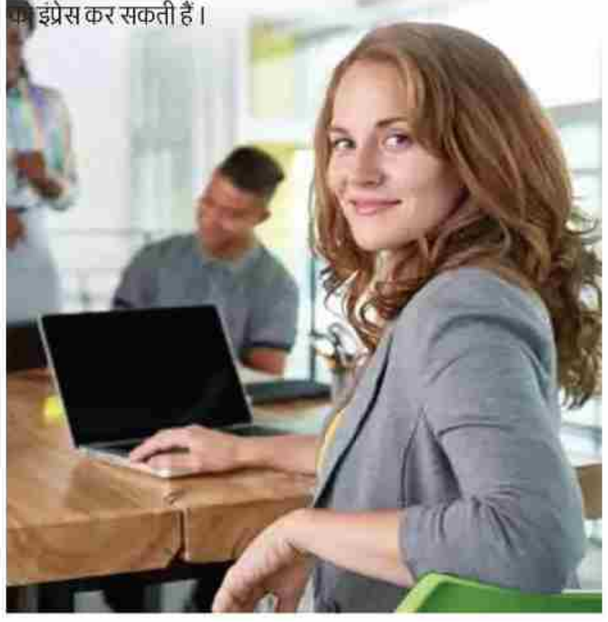

सार समाचार

कोविड-19 टीका लगवाने के बाद कसरत करने से बढती हैं एंटीबॉडी: अध्ययन

वाशिंगटन। कोविड-19 या किसी फ्लू से बचने के लिए टीकाकरण कराने के बाद 90 मिनट तक हल्की या मध्यम स्तर की कसरत करके शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ाई जा सकती हैं। एक अध्ययन में यह दावा किया गया है। इस अध्ययन के निष्कर्ष 'ब्रेन, बिहेवियर एंड इम्युनिटी' पत्रिका में प्रकाशित किए गए है। अध्ययन में शामिल जिन लोगों ने टीकाकरण कराने के बाद डेढ़ घंटे तक साइकिल चलाई या सैर की, उनमें आगामी चार सप्ताह में उन लोगों की तुलना में अधिक एंटीबॉडी बनीं, जिन्होंने टीकाकरण के बाद किसी प्रकार का व्यायाम नहीं किया था। अमेरिका स्थित 'आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी' के अनुसंधानकर्ताओं ने भी चूहों और ट्रेडमिल का इस्तेमाल करके इसी प्रकार का प्रयोग किया, जिसका निष्कर्ष भी समान निकला। आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मरियन कोहुट ने कहा कि इस बात के कई कारण हो सकते हैं कि लंबे समय तक हल्की या मध्यम स्तर की कसरत करने से शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता में सुधार क्यों होता है। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार, व्यायाम करने से रक्त प्रवाह बढ़ता है, जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं के संचार में मदद करता है और जब ये कोशिकाएं शरीर में प्रवाहित होती हैं, तो किसी बाहरी तत्व को बेहतर तरीके से उनके द्वारा पहचान लेने की संभावना अधिक होती है। कोहुट ने कहा, 'लेकिन इसका कारण जानने के लिए और अनुसंधान की आवश्यकता है। जब हम कसरत करते हैं, तो शरीर में चयापचय, जैव रासायनिक, न्यूरोएंडोक्राइन और (रक्त एवं कोशिका के) संचार स्तर पर कई बदलाव होते हैं।' उन्होंने कहा कि संभवत: इन कारकों के संयोजन के कारण एंडीबॉडी की मात्रा बढ़ती है।

यूक्रेन संकट: ऑस्ट्रेलिया ने चीन से रूस की निंदा करने का आग्रह किया

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को चीन से आग्रह किया कि वह यूक्रेन पर रूस के संभावित आक्रमण की निंदा करे। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि बीजिंग और मास्को ने घोषणा की है कि यूक्रेन की सीमा पर एक लाख रूसी सैनिकों के जमावड़े के बाद से वे (चीन और मास्को) और नजदीक आए हैं। मॉरिसन ने संसद में कहा, 'हमे उम्मीद है कि दुनिया के सभी देशों की सरकारें यूक्रेन के प्रति हिंसा के खतरे की निंदा करें।' उन्होंने कहा, 'हमें पता है कि चीन की सरकार, रूसी सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे पर एक दूसरे का सहयोग कर रही है और यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है चीन की सरकार ने उसकी निंदा नहीं की है।' मॉरिसन ने सभी सांसदों से अनुरोध किया कि वे यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई की निंदा करने के लिए चीनी सरकार से आग्रह करें और संयुक्त राष्ट्र द्वारा उचित कार्रवाई करने को स्वीकृति दें। ऑस्ट्रेलिया द्वारा चीन की आलोचना से दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास और बढ़ने की आशंका है। गौरतलब है कि चीन, ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। हाल के वर्षों में घरेलू राजनीति पर गोपनीय विदेशी हस्तक्षेप को गैर कानूनी करार देने, चीनी कंपनी हुआवे की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाने और कोविड महामारी के उद्भव की स्वतंत्र जांच कराने की मांग करने से ऑस्ट्रेलिया को चीन की नाराजगी झेलनी पड़ी, जिससे उसके व्यापार पर असर पड़ा है।

कनाडा में प्रदर्शनों से निपटने के लिए ट्रुडो ने आपातकालीन शक्तियों का किया इस्तेमाल

ओटावा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने कोविड-19 प्रतिबंधों के विरोध में ओटावा को पंगु बनाने वाले और सीमा पार यातायात को बाधित करने वाले ट्रक ड्राइवरों और अन्य लोगों के प्रदर्शन से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया है। ट्रुडो ने सेना का इस्तेमाल करने की संभावना से इनकार किया और सोमवार को कहा कि आपातकालीन कदम 'निश्चित समय सीमा के लिए उठाए जाएंगे, भौगोलिक आधार पर लागू किए जाएंगे और जिस खतरे से निपटने के लिए उन्हें लागू किया गया है, वे उसके अनुपात में एवं तार्किक तरीके से लागू किए जाएंगे।' ट्रुडो प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सेना बुलाने की अपील को अब तक खारिज करते आए हैं। बहरहाल उन्होंने यह कहा था कि अन्य सभी 'विकल्पों पर गौर किया गया है।' ट्रकों और अन्य वाहनों में हजारों प्रदर्शनकारियों ने ओटावा की सड़कों को पिछले दो सप्ताह से बाधित कर रखा है। ये प्रदर्शनकारी कोविड-19 टीका लगवाने की अनिवार्यता और महामारी के कारण लागू अन्य प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं। ट्रकों के काफिले ने ओंटारियो में विंडसर को अमेरिकी शहर डेट्रॉइट से जोड़ने वाले एम्बेसडर ब्रिज को अवरुद्ध कर दिया है जिससे दोनों देशों के बीच ऑटो पार्ट्स तथा अन्य उत्पादों का आयात-निर्यात बाधित हो गया है।

दक्षिण कोरिया में कोविड-19 के कारण रिकॉर्ड मौतें

सियोल । दक्षिण कोरिया में कोरोना संक्रमण के कारण मंगलवार को पिछले एक महीने में मौत के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपने नागरिकों को यहां यात्रा नहीं करने की सलाह दी है ।कोरोना के ओमीक्रोन स्वरूप के कारण द.कोरिया इनदिनों महामारी की भयावह लहर का सामना कर रहा है। कोरिया रोग नियंत्रण एवं रोकथाम एजेंसी (केडीसीए) ने बताया कि देश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 61 मरीजों की मौत हुई। इसके पहले 19 जनवरी को संक्रमण के कारण रिकॉर्ड 74 मरीजों की मौत हुई थी। एक महीने पहले देश में कोरोना के डेल्टा स्वरूप के कारण मामलों में वृद्धि हो रही थी, जबकि ओमीक्रोन के कारण संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। कोरिया रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी के मुताबिक, बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 57,177 नए मामले सामने आए। आगामी कुछ सप्ताहों में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है और मरने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि होने की आशंका है।

जापानी रेड आर्मी के सदस्यों की तलाश जारी

तोक्यो । तोक्यो पुलिस ने 1970 और 1980 के दशक में हुए हमलों में कथित भूमिका के लिए वांछित जापानी रेड आर्मी के सदस्यों की तलाश सोमवार को तेज कर दी। उम्रदराज आतंकवादियों की तस्वीरों के साथ वीडियो जारी कर चेतावनी दी गई है कि 'मामला अभी बंद नहीं हुआ है। वीडियो मध्य जापान के लॉज में 1972 के असामा सांसो बंधक संकट के 50 साल पूरा होने पर जारी किया गया। इस घटना में दो पुलिस अधिकारी गोलीबारी में मारे गए थे। वीडियो में कहा गया है,जापानी रेड आर्मी के सदस्य अभी फरार हैं, और वे आपके आस-पास कहीं भी मौजूद हो सकते हैं ।वीडियो में चेतावनी देकर कहा गया है, मामला अभी बंद नहीं हुआ है।' जापानी रेड आर्मी का फलस्तीनी उग्रवादियों के साथ संबंध था। इसका गठन 1971 में हुआ था, और इसने कई अंतरराष्ट्रीय हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 1975 में कुआलालंपुर, मलेशिया में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर कब्जा भी शामिल है। संगठन पर 1972 में तेल अवीव, इजराइल के बाहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गोलीबारी और ग्रेनेड हमले में संलिप्त होने का भी संदेह है। आतंकवादियों की पहचान का अभियान मई के अंत में जेल में बंद संगठन की नेता फुसाको शिगेनोबु (76) की निर्धारित रिहाई से कुछ महीने पहले शुरू हुआ है। शिगेनोबु को 1974 में नीदरलैंड के हेग में फ्रांसीसी दूतावास पर कब्जा करने की कार्रवाई का सरगना होने के आरोप में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

अमेरिका में घरेलू हिंसा में बचे हुए लोगों के समर्थक अरकांसा यूनिवर्सिटी के परिसर में प्रदर्शन करते हुए।

कश्मीर का अनसुलझा विवाद चिंता का विषय, इमरान ने फिर अलापा 'कश्मीर' राग

इस्लामाबाद। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अर्नगल प्रलाप बंद करने वाला नहीं है अब यहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि कश्मीर का अनसुलझा विवाद चिंता का विषय है और दोनों देशों को अच्छे पड़ोसी की तरह वार्ता की मेज पर इस मामले का समाधान करना चाहिए। खान ने मीडिया को दिए साक्षात्कार में कहा, 'अगर यह मुद्दा जारी रहता है तो हमेशा दोनों परमाणु शक्तियों के बीच संघर्ष होने की आशंका कायम रहेगी। तो आपके सवाल पर मेरा जवाब है, हां यह मुझे चिंतित करती है।' उन्होंने कहा, ह्यऔर हमारा एकमात्र मुद्दा कश्मीर है और हमें अच्छे पड़ोसी की तरह वार्ता की मेज पर इसका समाधान करना चाहिए ह्ल उल्लेखनीय है कि भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि उसकी इच्छा इस्लामाबाद के साथ आतंकवाद विद्वेष और हिंसा से मुक्त माहौल में सामान्य पड़ोसी की तरह संबंध स्थापित करने की है। भारत ने कहा कि यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वह आतंकवाद और विद्वेष मुक्त माहौल बनाए। भारत बार-बार स्पष्ट कर चुका है कि जम्मू-कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा था और हमेशा रहेगा। सीएनएन को दिए साक्षात्कार के दौरान पूछा गया कि क्या सीमा पर गलत आकलन से स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है? खान ने सहमति जताई कि कश्मीर में 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद उत्पन्न सैन्य गतिरोध बढ़ सकता था। उन्होंने कहा, 'यह आसानी से बढ़ सकता था।' पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि इसलिए उन्होंने तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे शक्तिशाली देश के प्रमुख होने के नाते आह्वान किया था कि 'यह बहुत अहम है कि हम इस कश्मीर मुद्दे का समाधान करें।' उन्होंने कहा, 'जैसे ही मेरी सरकार सत्ता में आई, पहला काम मैंने किया कि भारत से संपर्क किया और मैंने कहा कि देखिए आप एक कदम हमारी ओर बढ़ेंगे तो हम दो कदम आपकी ओर बढ़ाएंगे।'

जयशंकर के बयान से चीन को लगी मिर्ची, संबंधों के बिगड़ने के लिए भारत को बताने लगा जिम्मेदार

बीजिंग (एजेंसी)

चीन के भारत से डर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी हाल ही में क्वाड देशों ने बैठक की थी। जिसमें चीन ने भारत के बयान पर अपनी नजरें टिकाई रखी। जैसे ही क्वाड देशों की बैठक खत्म हुई भारत ने बयान दिया, जिसके बाद चीन अपनी असलियत पर उतर आया। यानी धमकी देने पड़ और इस बार की धमकी सुनकर तो सभी को बस हंसी ही आ जाएगी। दरअसल, क्वाड की अहम बैठक में जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को आइना दिखाया। उसके बाद चालबाज चीन ने अपना अहम बयान जारी किया।

चीन का बयान

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि सीमा मुद्दे पर चीन हमेशा कहता आया है कि हमें उन संधियों और समझौतों का पालन करना चाहिए जिन पर हमने हस्ताक्षर किए हैं। हम संयुक्त रूप से सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखते हैं। हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से संचार जारी रखेंगे। उन्होंने पूर्वी लद्दाख गतिरोध पर बीजिंग के अक्सर दोहराये गये रुख का जिक्र किया और कहा कि इसके लिए चीन जिम्मेदार नहीं है।

जयशंकर ने उठाए थे सवाल

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर मौजूदा स्थिति, चीन द्वारा सीमा पर सैनिकों को एकत्र न करने के लिखित समझौतों की अवहेलना करने के कारण पैदा हुई है। एस जयशंकर ने अपनी आस्ट्रेलियाई समकक्ष मारिस पायने के साथ मेलबर्न में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीमा पर सैनिक जमा नहीं करने का भारत के साथ 2020 में किये गये लिखित वादों का चीन द्वारा सम्मान नहीं किये जाने के चलते एलएसी पर यह स्थिति उत्पन्न हुई।

भारत क्वाड को आगे बढ़ाने वाली ताकत है: व्हाइट हाउस

वाशिंगटन (एजेंसी)

व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत क्वाड (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) को आगे बढ़ाने वाली ताकत और क्षेत्रीय विकास का इंजन है। उसने मेलबर्न में क्वाड समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद यह बात कही है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य देश हैं।

व्हाइट हाउस की प्रधान उप प्रेस सचिव कैरीन जीन पियरे ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'हम इस बात को मानते हैं कि भारत समान सोच रखने वाला साझेदार, दक्षिण एशिया एवं हिंद महासागर में अग्रणी, दक्षिण पूर्व एशिया में सक्रिय एवं उससे जुड़ा हुआ, क्वाड को आगे बढ़ाने वाली शक्ति और क्षेत्रीय विकास का एक इंजन है।' उन्होंने मेलबर्न में हुई बैठक के बारे में कहा, 'यह यूक्रेन में जारी रूस के संकट पर चर्चा करने का अवसर था। उन्होंने उस खतरे पर चर्चा की, जो रूस के कारण न केवल यूक्रेन के लिए, बल्कि क्षेत्र और दुनिया में सुरक्षा एवं समृद्धी का दशकों से आधार रही अंतरराष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था के लिए पैदा हुआ है।'

पियरे ने कहा कि अमेरिका एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी बनाना जारी रखेगा, जिसमें अमेरिका और भारत दक्षिण एशिया में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करें, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग करें और आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करें तथा हिंद प्रशांत को मुक्त एवं स्वतंत्र बनाने में योगदान दें। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में कहा था कि भारत किसी एक देश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन नहीं करता, बल्कि बहुपक्षीय प्रतिबंधों को मानता है। पियरे ने इस बयान को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया।

हिजाब विवाद में कूदा मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी, कहा मुस्लिमों की सुरक्षा तय करे भारत

रियाद (एजेंसी)

भारत के हिजाब विवाद में अब इस्लामिक देशों का संगठन ओआईसी भी कूद पड़ा है। इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) ने हिजाब विवाद, धर्म संसद और मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन निशाना बनाए जाने की खबरों को लेकर टिप्पणी की है। संगठन के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहिर ने संयुक्त राष्ट्र से इन मामलों को लेकर जरूरी कदम उठाने की अपील की है।

अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ओआईसी ने कहा, इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव ने उत्तराखंड के हरिद्वार में हिंदुत्व समर्थकों की ओर से मुसलमानों के नरसंहार के आह्वान, सोशल मीडिया साइट्स पर मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं, साथ ही कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने पर गहरी चिंता जताई है। इससे पहले पाकिस्तान और अमेरिका भी हिजाब विवाद पर टिप्पणी कर चुके हैं।

ट्वीट में कहा गया ओआईसी के महासचिव ने इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार परिषद से जरूरी कदम उठाने का आह्वान किया है। ओआईसी एक बार फिर भारत से आग्रह करता है कि मुस्लिम समुदाय के जीने के अधिकार की रक्षा करते हुए इसके सदस्यों के हितों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करे। साथ ही उनके खिलाफ हिंसा और नफरत जैसे अपराधों को भड़काने वालों और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाए।

यह पहली बार नहीं है कि जब मुस्लिम देशों के इस संगठन ने भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की है। इससे पहले भी ओआईसी कश्मीर पर जहर उगल चुका है। पिछले साल विशेष दूत युसेफ एल्डोबे ने कहा था कि ओआईसी कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करना जारी रखेगा। ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज दुनियाभर के मुसलमान मुल्कों का रहनुमा होने का दावा करता है। 25 सितंबर 1969 में बने इस संगठन का पाकिस्तान संस्थापक सदस्य है। दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। पाकिस्तान शुरू से ही इस संगठन का उपयोग भारत के खिलाफ करता आया है। चीन, पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान और ईराक में मुसलमानों की दुर्दशा के सवाल पर इस संगठन के मुंह पर चुप्पी छा जाती है।

मुंबई, पठानकोट, पुलवामा में आतंकवादी हमले करने वालों को पाकिस्तान का सहयोग मिल रहा है: भारत

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि दुनिया जानती है कि 2008 में मुंबई में, 2016 में पठानकोट में और 2019 में पुलवामा में हुए आतंकवादी हमलों को अंजाम देने वाले अपराधी कहां से आते हैं और यह 'दुख की बात' है कि इस प्रकार की 'कायराना' करतूत करने वाले पड़ोसी देश के सहयोग एवं आतिथ्य सत्कार का आनंद ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर राजेश परिहार ने सोमवार को कहा कि ठीक तीन साल पहले 14 फरवरी, 2019 को 40 बहादुर भारतीय सुरक्षा कर्मी पुलवामा में किए गए जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के 'कायराना आतंकवादी हमले' में शहीद हुए थे। परिहार ने दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के सदस्य देशों के साथ आतंकवाद-रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय (सीटीईडी) के काम पर खुली चर्चा के दौरान भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए कहा, 'दुनिया 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले, 2016 में पठानकोट आतंकवादी हमले और 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले की भयावहता की साक्षी बनी। हम सभी जानते हैं कि इन हमलों को अंजाम देने वाले हमलावर कहां से आए थे।' उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि यह 'खेदजनक' है कि इन हमलों के पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है और इन हमलों को अंजाम देने वाले हमलावर, इसमें सहयोग करने वाले और आर्थिक मदद देने वाले लोग अब भी आजाद घूम रहे हैं तथा 'देश के सहयोग एवं आतिथ्य-सत्कार का आनंद ले रहे हैं।' पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अलकायदा के मारे गए नेता ओसामा बिन लादेन को 'शहीद' कहा था। परिहार ने इसका जिक्र करते हुए कहा, 'आतंकवाद का यह केंद्र उन आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है, जिनका संबंध संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित 150 संगठनों एवं व्यक्तियों से है और इसके नेता आतंकवादियों की अकसर प्रशंसा करते हुए उन्हें 'शहीद' कहते हैं।' परिहार ने जोर देकर कहा कि भारत इन आतंकवादी हमलों के साजिशकताओं को न्याय के दायरे में लाने के लिए 'पूरी तरह प्रतिबद्ध' है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय 'आतंकवाद के केंद्र इस देश' से अपने क्षेत्र में सक्रिय और उसके नियंत्रण में काम कर रहे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ बिना किसी देरी के प्रभावी, विश्वसनीय, सत्यापन योग्य और मजबूत कार्रवाई करने को कहे। परिहार ने कहा, 'हमने ईसाइयों, हिंदुओं और सिखों समेत जातीय, सांप्रदायिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लगातार आतंकवादी हमले होते देखे हैं। हमारे पड़ोसी देश में अतिवादी विचारधारा के विकास को कट्टरपंथी संगठनों के संरक्षण दिए जाने से बल मिला है। देश द्वारा कट्टरपंथ और सांप्रदायिक विचारधारा को मुख्यधारा में लाने से इस क्षेत्र में आतंकवादी ढांचे के विकास के लिए एक उपयुक्त वातावरण भी उपलब्ध हुआ है।' उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक वैश्विक लड़ाई में आगे रहा है और आतंकवाद को ह्यह्यकतई बर्दाश्तह्लह्ल नहीं करने की नीति पर काम रहा है।

अमेरिका ने रूस को फिर चेतावनी दी-यूक्रेन पर आक्रमण के भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

वाशिंगटन (एजेंसी)

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने एक बार फिर रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने पर 'गंभीर परिणाम' भुगतने की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि क्रेमलिन रचनात्मक तौर पर चयन करता है तो कूटनीति का मार्ग अभी भी उपलब्ध है।

व्हाइट हाउस की प्रधान उप प्रेस सचिव कैरीन जीन पियरे ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि अमेरिकासंकट को कम करने के लिए एक राजनयिक समाधान तक पहुंचने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा जैसा कि आप सभी जानते हैं, सप्ताहांत में बाइडन ने (रूस के) राष्ट्रपति पुतिन के साथ बात की और हम अपने सहयोगियों तथा भागीदारों के साथ पूर्ण तालमेल बनाते हुए रूस सरकार के साथ संपर्क में हैं।' रूस ने यूक्रेन की सीमा के समीप करीब 100,000 सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है। इस कदम पर पश्चिम देश उसे चेतावनी दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उसका इरादा यूक्रेन पर हमला करने का है। हालांकि रूस ने बार-बार इनकार किया है कि उसकी यूक्रेन पर हमला करने की कोई योजना है। जीन पियरे ने कहा, 'अगर रूस इस मुद्दे पर रचनात्मक रुख अपनाताहै तो कूटनीति का रास्ता उपलब्ध है। हालांकि, हम रूस द्वारा जमीन पर उठाए जा रहे कदमों को देखते हुए इस बात की संभावनाओं को लेकर स्पष्ट हैं।' उन्होंने कहा कि बाइडन ने स्थिति पर चर्चा करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से संपर्क किया। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं (बाइडन एवं जॉनसन) ने यूक्रेन और रूस के साथ अपने हालिया राजनयिक संबंधों पर चर्चा की। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने यूक्रेन की सीमाओं पर रूस के निरंतर सैन्य जमावड़े के जवाब में चल रहे राजनयिक और प्रतिरोधक प्रयासों की भी समीक्षा की तथा यूक्रेन की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक बार फिर अपना अपना समर्थन दोहराया।

व्हाइट हाउस ने कहा, 'दोनों नेताओं ने नाटो के पूर्वी हिस्से पर रक्षात्मक मुद्रा को मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा की और सहयोगियों एवं भागीदारों के बीच निरंतर घनिष्ठ समन्वय पर बल दिया, जिसमें रूस द्वारा हमले की स्थिति में उस पर गंभीर कार्रवाई को लेकर तत्परता बरतना भी शामिल है।' व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन के दौरान जीन पियरे ने कहा कि उनकी (अमेरिका प्रशासन की) इस बात पर पैनी निगाह है कि कब आक्रमण होता है। उन्होंने कहा, 'हम अपनी खुफिया जानकारी के किसी भी विवरण पर टिप्पणी नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि यह इस सप्ताह शुरू हो सकता है, ऐसी कई अटकलें हैं कि यह ओलंपिक के बाद होगा। यह स्पष्ट नहीं है कि रूस कौन सा रास्ता चुनेगा।' पियरे ने कहा कि अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति बाइडन ने इस सप्ताह के अंत में पुतिन के साथ अपनी बातचीत में यह स्पष्ट कर दिया कि यदि रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है, तो अमेरिका अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ मिलकर निर्णायक जवाब देगा और रूस को त्वरित और गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।'

उन्होंने कहा कि बाइडन ने एक बार फिर कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले से व्यापक मानवीय त्रासदी होगी और रूस का कद बहुत घट जाएगा। इससे इतर एक अलग संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने घोषणा की है कि देश के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बेल्जियम, पोलैंड और लिथुआनिया की यात्रा करेंगे। वह यूक्रेन और उसके आसपास रूस के सैन्य जमावड़े पर चर्चा करने के लिए संबद्ध रक्षा मंत्रियों और नाटो नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच, ह्यएपीह्ल की खबर के अनुसार क्रेमलिन (रूस के राष्ट्रपति कार्यालय) ने सोमवार को संकेत दिया कि वह सुरक्षा शिकायतों को लेकर पश्चिमी देशों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, जिससे यह उम्मीद जगी है कि रूस यूक्रेन पर फिलहाल आक्रमण नहीं करेगा। हालांकि, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंशा पर सवाल बना हुआ है और शीत युद्ध के बाद से सबसे खराब तनाव के बीच देश अपने राजनयिकों को वापस बुला रहे हैं और संभावित आसन्न युद्ध को लेकर सतर्क हैं। रूस ने इस बात की गारंटी मांगी है कि नाटो यूक्रेन या सोवियत संघ के पूर्व देशों को अपने साथ नहीं जोड़ेगा और यह कि वह सोवियत संघ के पूर्व देशों से अपने सैनिकों को वापस बुलायेगा।

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में भी जीत का सिलसिला बरकरार रखने उतरेगी टीम इंडिया

कोलकाता (एजेंसी)।

भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को यहां मेहमान टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 क्रिकेट मुकाबले में जीत के इरादे से उतरेगी। एकदिवसीय सीरीज में शानदार जीत से उत्साहित भारतीय टीम इस सीरीज में भी जीत दर्ज करना चाहेगी। यह सीरीज आगामी टी20 विश्वकप को देखते हुए भी अहम है , इसलिए इसमें दोनो ही टीमें बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगी। इसी कारण भारतीय टीम ने इस सीरीज में कई युवा प्रतिभाओं को अवसर दिया है। भारतीय टीम प्रबंधन का लक्ष्य इस सीरीज के जरिये टीम के लिए सही संयोजन तलाशना रहेगा।

भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के अलावा सभी अन्य खिलाड़ी भी इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। टीम इंडिया सलामी जोड़ी, मध्यक्रम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को लेकर विशेष रणनीति भी तैयार करना चाहेगी। भारतीय टीम में काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी उपस्थित हैं।

भारतीय टीम में शामिल कई खिलाड़ियों श्रेयस अय्यर , हर्षल पटेल और शारदुल ठाकुर आदि को बड़ी रकम मिली है। ऐसे में इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें होंगी। इसके अलावा भारतीय टीम को लोकेश राहुल का भी विकल्प तलाशना होगा। राहुल मांसपेशियों में खिंचाव के इस सीरीज से बाहर हो गये हैं। ऐसे में उनकी जगह ऋषभ पंत को उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। राहुल के बाहर होने के कारण ईशान किशन को रोहित के साथ पारी की शुरुआत का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा एक अन्य बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ या वेंकटेश अय्यर को भी यह जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं पूर्व कप्तान विराट कोहली अगर रोहित के साथ पारी की शुरुआत करते हैं तो यह रोमांचक होगा। कोहली पिछले कुछ समय से उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और उन्होंने पिछला शतक इसी मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ दिन-रात्रि टेस्ट में नवंबर 2019 में लगाया था। वहीं मध्यक्रम में बल्लेबाज सूर्यकुमार एकदिवसीय श्रृंखला में 52 की औसत से 104 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे हैं जबकि अय्यर ने तीसरे एकदिवसीय में 80 रन की शानदार पारी खेली थी। निचले क्रम में भारत के पास शारदुल ठाकुर, दीपक चाहर और हर्षल पटेल के रूप में अच्छे खिलाड़ी हैं। स्पिन की जिम्मेदारी युजवेंद्र चहल पर रहेगी। चहल ने एकदिवसीय श्रृंखला में वापसी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। स्पिनर वाशिंगटन सुंदर के पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण श्रृंखला से बाहर होने के कारण युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को पदार्पण का मौका मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर एकदिवसीय श्रृंखला में खराब प्रदर्शन को भूलकर कप्तान कीरोन पोलार्ड की वेस्टइंडीज टीम इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी। वैसे भी इंडीज खिलाड़ियों का यह पसंदीदा प्रारुप है। वेस्टइंडीज के पास कई मैच विजेता खिलाड़ी जेसन होल्डर , ओडियन स्मिथ, अकील हुसैन और पोलार्ड हैं। ऐसे में उसे कमजोर नहीं माना सकता है।

दोनो टीमें इस प्रकार हैं

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), इशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, वेंकटेश अय्यर, दीपक चाहर, शारदुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार, अवेश खान, हर्षल पटेल, रुतुराज गायकवाड़, दीपक हुड्डा, कुलदीप यादव और हरप्रीत बरार।

वेस्टइंडीज: कीरोन पोलार्ड (कप्तान), निकोलस पूरन, फैबियन एलेन, डेरेन ब्रावो, रोस्टन चेज, शेल्डन कॉटरेल, डोमीनिक ड्रेक्स, जेसन होल्डर, शाई होप, अकील हुसैन, ब्रैंडन किंग, रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड, ओडियन स्मिथ, काइल मेयर्स, हेडन वॉल्श जूनियर।

जोकोविच की जिद! खिताब खो दूंगा पर नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन

नई दिल्ली (एजेंसी)।

20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता एवं दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने मंगलवार को कहा कि वह कोरोना वैक्सीन लगाने के बजाय टेनिस प्रतियोगिताओं में भाग लेने का त्याग करने के लिए तैयार हैं।

जोकोविच ने इस बारे में कि क्या वह कोरोना वैक्सीन पर अपने रुख के चलते आगामी विंबलडन और फ्रेंच ओपन जैसे टेनिस टूर्नामेंटों का त्याग करने को तैयार हैं, कहा, 'हां, यही वह कीमत है जो मैं चुकाने को तैयार हूं।'

दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी ने बीबीसी के साथ एक साक्षात्कार में कहा, 'मैं कभी भी टीकाकरण के खिलाफ नहीं था, लेकिन आप अपने शरीर में क्या डालते हैं, मैं इसे चुनने की स्वतंत्रता का समर्थन करता हूं। अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने के सिद्धांत मेरे लिए किसी भी खिताब या किसी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

मैं जितना संभव हो सके अपने शरीर के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि विश्व स्तर पर हर कोई इस वायरस से निपटने के लिए बड़ा प्रयास करने की कोशिश कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही इस वायरस का अंत हो जाएगा।'

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के आप्रवासन मंत्री एलेक्स हॉक ने जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने टीकाकरण की स्थिति नहीं बताई थी। उन्हें ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था और उन्हें कई दिन आप्रवासन केंद्र में बिताने पड़े थे। बाद में ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने उन्हें नजरबंदी से रिहा करने का आदेश दिया था।

भारत-श्रीलंका सीरीज के लिए बीसीसीआई ने जारी किया नया शेड्यूल्ड, लखनऊ में होगा पहला टी20 मुकाबला

बेंगलुरू। (एजेंसी)।

भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला खेल रही है। वेस्टइंडीज के बाद भारतीय टीम का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंकाई टीम भारत के दौरे पर आएगी। हालांकि बीसीसीआई ने आज श्रीलंका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के लिए शेड्यूल में बदलाव की घोषणा की है। बीसीसीआई की ओर से जारी नए शेड्यूल के मुताबिक भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ पहले टी-20 मुकाबला खेलेगी। श्रीलंका के खिलाफ तीन टी20 मैच होंगे। सबसे खास बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा।

बीसीसीआई की ओर से जारी नए शेड्यूल के मुताबिक टी20 सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा। लखनऊ में 24 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम टी20 मुकाबला खेलेगी। इसके बाद 2 टी20 के मुकाबले धर्मशाला में होंगे। श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच भी है। पहला टेस्ट मैच मोहाली में होगा जबकि दूसरा टेस्ट डे नाईट होगा जो कि बेंगलुरु में होगा। मोहाली में भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच इतिहासिक हो सकता है। अगर विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के लिए उपलब्ध होते हैं तो वह उनका 100वां टेस्ट मैच होगा।

संशोधित कार्यक्रम इस प्रकार से है

20 फरवरी- पहला टी-20 मैच, लखनऊ

26 फरवरी - दूसरा टी- 20 मैच, धर्मशाला

27 फरवरी- तीसरा टी20 मैच, धर्मशाला

4 से 8 मार्च, पहला टेस्ट, मोहाली

12 से 16 मार्च, दूसरा डे नाइट टेस्ट, बेंगलुरु

कीगन और हीथर को 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड'

दुबई । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी (आईसीसी) ने पुरुष वर्ग से दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कीगन पीटरसन और महिला वर्ग से इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट को जनवरी महीने के लिए 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड' दिया है। इस अवार्ड के लिए पुरुष और महिला वर्ग में कुल 6 खिलाड़ियों को नामांकित किया गया था। इसके लिए दक्षिण अफ्रीकी युवा आक्रामक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस और बांग्लादेश के तेज गेंदबाज इबादत हुसैन भी दौड़ में शामिल थे पर कीगन इनपर भारी पड़े हैं। कीगन ने हाल ही में भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की थी। उन्होंने इस टेस्ट की लगातार तीन पारियों मे अर्धशतक लगाये थे। उन्होंने सीरीज में 61 की औसत से 276 रन बनाए थे। इसी प्रदर्शन के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का इनाम भी मिला था। वहीं महिला वर्ग में विजेता हीथर ने अवार्ड की दौड़ में वेस्टइंडीज की डियांड्रा डॉटिन और श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को पीछे छोड़ा। नाइट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला एशेज सीरीज के एकमात्र टेस्ट मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी की थी।

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे एक दिवसीय मैचः श्रृंखला में 2-0 की बनाई बढ़त

दूसरे महिला वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को तीन विकेट से दी शिकस्त

वींसटाउन। (एजेंसी)।

भारत को अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी की कमी खली जिनकी गैरमौजूदगी में मंगलवार को यहां टीम दूसरे महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 270 रन के स्कोर का बचाव करने में विफल रही और उसे तीन विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने इस जीत के साथ पांच मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली है। दीप्ति शर्मा ने 52 रन देकर चार विकेट चटकाए जबकि पूनम यादव, राजेश्वरी गायकवाड़ और हरमनप्रीत कौर की स्पिन तिकड़ी ने एक-एक विकेट हासिल किया लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकी। भारत को झूलन की कमी खेली क्योंकि पूजा वस्त्रकार और पदार्पण कर रही सिमरन बहादुर की तेज गेंदबाजी जोड़ी ने काफी रन लुटाए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।

युवा प्रतिभाओं को मौका देने के लिए झूलन को आराम दिया गया था। स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना लंबे पृथकवास के कारण इस मुकाबले में भी नहीं खेल सकी। उनका पृथकवास मंगलवार को ही पूरा हुआ। भारत ने कप्तान मिताली राज (नाबाद 66), रिचा घोष (65) और सलामी बल्लेबाज साभिनेनी मेघना (49) की पारियों की बदौलत छह विकेट पर 270 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। न्यूजीलैंड ने इसके जवाब में अमेलिया केर (नाबाद 119) के शतक और मैडी ग्रीन (52) के साथ उनकी चौथे विकेट की 128 रन की साझेदारी की बदौलत 49 ओवर में सात विकेट पर 273 रन बनाकर जीत दर्ज की। भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत करते हुए नौवें ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 55 रन पर तीन विकेट कर दिया था लेकिन अमेलिया और ग्रीन ने 24.4 ओवर तक क्रीज पर टिककर मेहमान टीम की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ग्रीन को 23 रन के स्कोर पर तानिया भाटिया ने जीवनदान दिया जबकि अमेलिया भी कुछ मौकों पर भाग्यशाली रही। न्यूजीलैंड ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 10वें ओवर से पहले ही सोफी डिवाइन (33), पहले मैच में शतक जड़ने वाली सूजी बेट्स (16) और कप्तान ऐमी सेटरथवेट (00) के विकेट गंवा दिए। अमेलिया और ग्रीन ने हालांकि चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी करके न्यूजीलैंड की जीत का मंच तैयार किया। ग्रीन जब पवेलियन लौटी तब टीम को 16.3 ओवर में जीत के लिए 88 रन की दरकार थी लेकिन अमेलिया ने टीम को जीत दिला दी।

इससे पहले कप्तान मिताली राज ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए नाबाद 66 रन बनाए जबकि रिचा घोष ने भी अर्धशतक जड़ा। पहले मैच में हार के दौरान 59 रन बनाने वाली मिताली ने 81 गेंद की अपनी पारी में तीन चौके मारे। रिचा ने आक्रामक बल्लेबाजी की और 70 गेंद की अपनी पारी में छह चौके और एक छक्का मारा। मिताली और रिचा ने पांचवें विकेट के लिए 17.4 ओवर में 108 रन की साझेदारी की जिससे टीम चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रही। सलामी बल्लेबाज मेघना ने शेफाली वर्मा (24) के साथ पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। शेफाली हालांकि अच्छी शुरुआत को एक बार फिर बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रही। पहले मैच में 41 रन बनाने वाली यस्तिका भाटिया ने 38 गेंद में 31 रनबनाए। हरमनप्रीत कौर का लचर प्रदर्शन जारी रहा और वह 18 गेंद में सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौटी। न्यूजीलैंड की ओर से सोफी डिवाइन ने 42 रन देकर दो विकेट चटकाए।

ब्राजील और अर्जेंटीना फिर खेलें क्वालीफायर मैच : फीफा

लंदन । विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था (फीफा) ने ब्राजील और अर्जेंटीना को फिर से विश्व कप क्वालीफायर मैच खेलने को कहा है। इससे पहले यह मैच रद्द कर दिया गया था क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में खेलने वाले अर्जेंटीना के चार खिलाड़ियों पर सितंबर में साओ पाउलो में रखे मैच के लिए कोरोना पृथकवास के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगा था। इन चारों ने इस बात को नहीं बताया था कि वह इससे पहले 14 दिन के लिए ब्रिटेन में लाल सूची में रखे गये थे। फीफा ने कहा कि अर्जेंटीना के एमिलियानो बेंडिया, एमिलियानो मार्टिनेज, जियोवानी लो सेल्सो और क्रिस्टियन रोमेरो ने फीफा के फुटबॉल की वापसी से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। इस कारण उनपर दो मैचों का प्रतिबंध लगाया गया है। ब्राजील के स्वास्थ्य अधिकारियों ने तब स्टेडियम में जाकर मैच रुकवा दिया था। वहीं फीफा ने सुरक्षा से संबंधित नियमों के उल्लंघन और मैच रद्द करने के लिये ब्राजील फुटबॉल संघ पर लगभग छह लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया था।

स्केटर अवॉर्ड पर आईओसी ने कहा- सही लोगों को दें मेडल

बीजिंग। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के सदस्य डेनिस ओसवाल्ड ने कहा कि संगठन ने बीजिंग में खेलों के टीम फिगर स्केटिंग टूर्नामेंट के 'सही व्यक्ति' को ही पुरस्कार दिया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि विजेताओं को पदक प्रदान करने के लिए पुरस्कार देने का समारोह स्थगित कर दिया गया है। ओसवाल्ड ने कहा, 'हमने महसूस किया कि पदक समारोह के बारे में फैसला करने से पहले मामले पर स्पष्टता होने तक इंतजार करना सुरक्षित है।' उन्होंने यह भी कहा कि आईओसी 'निष्कलंक' एथलीटों को दंडित नहीं कर सकता, भले ही वे रूस से हों। गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को खेल के लिए पंचाट न्यायालय (सीएएस) ने रूसी स्केटर कामिला वलीवा के संबंध में आईओसी अंतरराष्ट्रीय स्केटिंग संघ (आईएसयू) और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की अपील को खारिज कर दिया और इसके साथ ही वलीवा के बीजिंग ओलंपिक में महिला एकल स्पर्धा में भाग लेने का रास्ता भी खुल गया।

राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए मीराबाई ने बढ़ाया वजन, इस नई कैटागिरी में खेलेंगी

नई दिल्ली । ओलिम्पिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू अगले राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किग्रा भार वर्ग में उतरेंगी। हालांकि चानू ने 49 किग्रा भार वर्ग में पिछले साल टोक्यो ओलिम्पिक खेलों का रजत पदक जीता था। उनके नाम पर क्लीन एवं जर्क में विश्व रिकार्ड भी है। 48 किग्रा वर्ग में भी वह विश्व चैम्पियनशिप 2017 का गोल्ड जीत चुकी हैं। उन्हें 2014 और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में इसी भार वर्ग में क्रमशः रजत और स्वर्ण पदक मिला था। लेकिन अब वह 55 किग्रा वर्ग में उतरेंगी। नए फैसले पर मुख्य कोच विजय शर्मा और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ को लगता है कि 27 वर्षीय चानू के पास 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में हमवतन सोरोखैबाम बिंद्यारानी देवी की तुलना में 55 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने का बेहतर मौका रहेगा। बिंद्यारानी ने पिछले दिसंबर में राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता था। चानू ने कहा कि हमारी (कोच और महासंघ) बैठक हुई और हमने चर्चा की कि भारत को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के प्रत्येक भार वर्ग में पदक हासिल करना चाहिए। मीराबाई ने कहा कि हमारे पास 4 से 5 स्वर्ण पदक जीतने का मौका रहेगा और इसलिए हमने फैसला किया कि मैं 55 किग्रा भार वर्ग में भाग लूंगी, ताकि हम इस भार वर्ग में एक स्वर्ण पदक जीत सकें। भारत के लिए 49 किग्रा वर्ग में झिली डालबेहरा उतरेंगी। उन्होंने राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता था। चानू का 49 किग्रा में स्वर्ण पदक जीतना तय माना जा रहा था लेकिन 55 किग्रा में सोने का तमगा जीतने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने फैसले पर मीराबाई ने कहा- मैं अपना वजन 50 से 51 किग्रा तक ही रखूंगी जो कि मेरा सामान्य वजन है।

आईसीसी वनडे रैंकिंग में कप्तान मिताली राज जलवा बरकरार

दुबई (एजेंसी)।

भारतीय कप्तान मिताली राज ने मंगलवार को जारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की महिला वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है जबकि भारत के खिलाफ पहले वनडे में शानदार प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड की बल्लेबाज ऐमी सेटरथवेट तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं।

क्वीन्सटाउन में पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत की 62 रन की हार के दौरान मिताली ने 73 गेंद में 59 रन बनाए। ऐमी ने 67 गेंद में 63 रन की पारी खेली और सलामी बल्लेबाज सूजी बेट्स के साथ तीसरे विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी की। उन्हें 13 रेटिंग अंक का फायदा हुआ जिससे उन्होंने आस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पछाड़ा। आस्ट्रेलिया की एलिसा हीली 749 अंक के साथ शीर्ष पर चल रही हैं जबकि मिताली के 744 अंक हैं। ऐमी के मिताली से 15 अंक कम हैं। बेट्स के 11वें एकदिवसीय शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई।

इस प्रदर्शन से वह छह महीने में पहली बार शीर्ष 20 बल्लेबाजों में शामिल हो गई हैं। साप्ताहिक अपडेट में बेट्स पांच स्थान की छलांग के साथ 17वें पायदान पर हैं। दूसरी तरफ आस्ट्रेलिया ने अपनी एशेज खिताबी जीत को आगे बढ़ाते हुए पिछले हफ्ते मेलबर्न में अंतिम वनडे में आसान जीत दर्ज की। इंग्लैंड के लिए अर्धशतक जड़ने वाली टैमी ब्युमोंट और मेग लेनिंग तीन-तीन स्थान के फायदे के साथ क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। दोनों के बीच सिर्फ एक रेटिंग अंक का अंतर है।

गेंदबाजी सूची में इंग्लैंड की सोफी एकलेस्टोन एक स्थान के फायदे से दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। उन्होंने आस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम वनडे में 18 रन देकर एक विकेट चटकाया। उनके पास वनडे और टी20 दोनों गेंदबाजी रैंकिंग में एक ही समय में नंबर एक गेंदबाज बनने का मौका है। एलिस पैरी को अपने आलराउंड प्रदर्शन की बदौलत गेंदबाजी रैंकिंग में तीन स्थान का फायदा हुआ है।

उन्होंने ऑलराउंडर की सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद नैट स्किवर पर 87 अंक की बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड की लिया ताहुहु चार स्थान के फायदे से 13वें जबकि भारत की राजेश्वरी गायकवाड़ पाचं स्थान आगे बढ़कर 16वें स्थान पर हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में बेथ मूनी ने तीसरी बार बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर जगह बनाई। उनकी कप्तान मेग लेनिंग एक स्थान के फायदे से दूसरे स्थान पर हैं। भारत की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड की गेंदबाज अमेलिया केर पांच स्थान के फायदे से आठवें जबकि उनकी बहन जेस केर 16 स्थान के फायदे से 34वें स्थान पर हैं।

ऑक्शन पर बोले रोहित शर्मा- मेरा ध्यान आईपीएल पर नहीं, टीम इंडिया पर है

कोलकाता। ईशान किशन या श्रेयस अय्यर को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपनी टीमों में विशेष भूमिका निभाने के लिये मोटी रकम देकर खरीदा गया लेकिन इस पर तब गौर नहीं किया जाएगा जब कप्तान रोहित शर्मा इस साल आस्ट्रेलिया में होने वाले विश्व कप को ध्यान में रखकर भारतीय टी20 टीम के बारे में फैसला करेंगे। भारत के वर्तमान कप्तान को 2011 में इसी तरह से मुंबई इंडियंस ने मोटी रकम में खरीदा था और वह जानते हैं कि किशन (15.25 करोड़ रुपए) और श्रेयस अय्यर (12.25 करोड़ रुपए) भी नीलामी के दौरान भावनाओं के ज्वार से गुजरे होंगे। रोहित ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच पर कहा कि सभी जानते हैं उन पर भावनाएं हावी रही होंगी। अब नीलामी समाप्त हो चुकी है और ध्यान राष्ट्रीय टीम पर है तथा टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों को इस बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया है। रोहित ने कहा कि कल हमारी प्रत्येक खिलाड़ी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई और हमने उनसे 'नीले रंग' (भारतीय टीम की जर्सी का रंग) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जो कि बेहद महत्वपूर्ण है।

दोषी ठहराये जाने के बाद 7वीं बार जेल जायेंगे लालू

रांची, 15 फरवरी (एजेन्सी)। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सातवीं बार जेल जायेंगे। रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में मंगलवार को दोषी करार दिया है।

इसके तुरंत बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया है। लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई अदालत में दरख्वास्त लगाई है कि उनका स्वास्थ्य बेहद खराब है। इस आधार पर उन्हें जमानत दी जाये या न्यायिक हिरासत में रिम्स (राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) भेजा जाये। अदालत इस दख्वास्त पर अपराह्न 2 बजे सुनवाई करेगी।

इस मामले में लालू प्रसाद यादव को कितने वर्षों की सजा होती है, इसपर अदालत आगामी 21 फरवरी को फैसला करेगी। लालू प्रसाद यादव के अलावा 74 अन्य अभियुक्तों को भी अदालत ने दोषी पाया है, जबकि 24 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। दोषी ठहराये गये अभियुक्तों में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, बिहार की लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत भी शामिल हैं। 36 अभियुक्तों को तीन वर्ष तक की सजा सुनायी गयी है। दोषी ठहराये गये सभी अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत ने जिन अभियुक्तों को बरी किया है, उनमें राजेन्द्र पांडे, साकेत, दीनानाथ सहाय, रामसेवक साहू, एनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, सैरून्निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा, निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुनील श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु और डॉ कामेश्वर प्रसाद शामिल हैं।

बता दें कि 26 साल तक चले इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अभियोजन की ओर से कुल 575 लोगों की गवाही कराई गई, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से 25 गवाह पेश किये गये। इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कुल 15 ट्रंक दस्तावेज अदालत में पेश किये थे। पशुपालन विभाग में हुए इस घोटाले में सांढ़, भैंस, गाय, बछिया, बकरी और भेड़ आदि पशुओं और उनके लिए चारे की फर्जी तरीके से ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध रूप से निकासी की गयी। जिन गाड़ियों से पशुओं और उनके चारे की ट्रांसपोर्टिंग का ब्योरा सरकारी दस्तावेज में दर्ज किया था, जांच के दौरान उन्हें फर्जी पाया गया। जिन गाड़ियों से पशुओं को ढोने की बात कही गयी थी, उन गाड़ियों के नंबर स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल के निकले।

बहुचर्चित चारा घोटाले केइस पांचवें मामले में रांची के डोरंडा थाने में वर्ष 1996 में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। बाद में सीबीआई ने यह केस टेकओवर कर लिया। मुकदमा संख्या आरसी-47 ए/96 में शुरुआत में कुल 170 लोग आरोपी थे। इनमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि आठ आरोपियों को सीबीआई ने सरकारी गवाह बना लिया। दो आरोपियों ने अदालत का फैसला आने के पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया। छह आरोपी आज तक फरार हैं।

यह चारा घोटाले से जुड़ा पांचवां मुकदमा है, जिसमें अदालत ने उन्हें दोषी माना है। इसके पहले चारा घोटाले के चार मुकदमों में अदालत ने लालू प्रसाद यादव को कुल मिलाकर साढ़े 27 साल की सजा दी है, जबकि एक करोड़ रुपए का जुर्माना भी उन्हें भरना पड़ा।

चारा घोटाले के सभी मामले 1990 से 1996 के बीच के हैं। बिहार के सीएजी (मुख्य लेखा परीक्षक) ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को समय-समय पर भेजी थी लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

सीबीआई ने अदालत में इस आरोप के पक्ष में दस्तावेज पेश किये कि मुख्यमंत्री पर रहे लालू यादव ने पूरे मामले की जानकारी रखते हुए भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। कई साल तक वह खुद ही राज्य के वित्त मंत्री भी थे, और उनकी मंजूरी पर ही फर्जी बिलों के आधारराशि की निकासी की गयी। चारा घोटाले के चार मामलों में सजा होने के चलते राजद सुप्रीमो को आधा दर्जन बार जेल जाना पड़ा। इन सभी मामलों में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली है।

जैसी करनी वैसी भरनी : सुशील मोदी

लखनऊ, 15 फरवरी (एजेन्सी)। सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को 139 करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को दोषी करार दिया है। इस मामले में 21 फरवरी को सजा का ऐलान होगा। बता दें कि चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में पहले ही लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं। यह चारा घोटाले के सबसे बड़ा और आखिरी मामला है। इस पर बीजेपी नेता बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है।

उन्होंने कहा, 'इस मामले को हमने ही उजागर किया था, पटना हाईकोर्ट की निगरानी में अगर जांच न होती तो ये कभी सामने नहीं आता। जब ये घोटाला हुआ तब लालू मुख्यमंत्री भी थे वित्त मंत्री भी थे। उनकी पूरी मिली भगत थी। इसलिए जो भी फैसला हुआ है, वह स्वागत योग्य है। इससे समाज के लिए एक मैसेज है कि पद पर रहते हुए जो भी लोग गरीबों को लूटने का काम करेंगे। उनको सजा मिलेगी। जैसी करनी वैसी भरनी।'

उन्होंने आगे कहा, 'लालू यादव ने जिस तरह सत्ता में रहते हुए गरीबों को लूटा उसी का परिणाम है कि पांचवें केस में दोषी करार दिए गए हैं।' उन्होंने कहा, 'हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। उम्मीद है कि न्यायपालिका लालू प्रसाद यादव की सेहत और उम्र का ध्यान रखते हुए सजा पर फैसला सुनाएगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कम से कम सजा मिले। लालू यादव ने हमेशा कहा है कि उन्हें फंसाया गया है। पहले दिन से वह यही कह रहे हैं।'

महाभारत वाला सैफई खानदान : सीएम योगी

लखनऊ, 15 फरवरी (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक बार फिर समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि संकट के समय ये लोग कहीं नहीं दिखते। सीएम योगी ने यह भी कहा कि यह सबके साथ की बात करते हैं, लेकिन विकास सिर्फ सैफई खानदान का करते हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''संकट के समय में क्या ये चाचा-भतीजा (अखिलेश-शिवपाल) कहीं दिखे? जब भी संकट आता है तो यह सैफई खानदान, जिसमें महाभारत के सभी रिश्ते दिखते हैं, कहीं नहीं दिखता है। उनका नारा है 'सबका साथ पर सिर्फ सैफई खानदान का विकास।''

इटावा, भरथना और जसवंतनगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''जो लोग इटावा को अपनी बपौती मान लिए थे, क्या वे कोरोना काल में आए? कभी हाल चाल लिया? इनसे कोई उम्मीद है क्या?''

सीएम योगी ने कहा, ''पांच साल पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, बमबाजी होती थी, गुंडा टैक्स वसूली होता था, अराजकता चरम पर थी, सबकुछ एक खानदान की बपौती थी। जिस जमीन और संपत्ति की ओर उन्होंने इशारा किया, शाम को उस गरीब को उजाड़कर अपनी संपत्ति बनाने की कोशिश करते थे।''

सपा, बसपा ने चरमराई यूपी की अर्थव्यवस्था : अमित शाह

औरैया, 15 फरवरी (एजेन्सी)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चरमराने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राज्य में पांच साल में बदलाव लाने का श्रेय दिया। शाह ने कहा कि 2022 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथ मजबूत करने और योगी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए है।

अमित शाह ने औरैया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा और बसपा के बबुआ और बुआ दोनों ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया था, देश में सातवें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था थी जिसे योगी जी पांच साल में दूसरे स्थान पर लाये हैं,पांच साल के लिए एक और मौका दें और इसे पहले स्थान पर ले जाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सफलता का दावा करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या कोई माफिया आपको कहीं भी परेशान कर सकता है? क्या कोई आपकी जमीन पर कब्जा कर सकता है? माताओं और बहनों के सम्मान के साथ क्या अब कोई खेल सकता है? योगी जी ने माफियाओं का उप्र से पलायन सुनिश्चित किया है।

गृहमंत्री उन्होंने सपा प्रमुख पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने पूछा था कि क्या हुआ है (भाजपा सरकार के पांच साल के दौरान), जिसने पीला चश्मा लगाया है, उसे सब कुछ पीला दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि योगी जी के कार्यकाल में डकैती के मामलों में 72 प्रतिशत, लूट में 62 प्रतिशत, हत्या में 31 प्रतिशत और बलात्कार के मामलों में 50 प्रतिशत तक की कमी आई है। पूर्ववर्ती सरकार पर हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में कट्टे बनते थे लेकिन अब भाजपा सरकार के दौरान गोले बन रहे हैं जो पाकिस्तान पर दागे जाएंगे। भाजपा सरकार यह बदलाव लेकर आई है।

अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि जब सपा-बसपा ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह सरकार का समर्थन किया था, पाकिस्तान से घुसपैठ हुई और हमारे सैनिकों का सिर काट दिया गया, लेकिन हमारे मौनी बाबा की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन मोदी ने सत्ता में आने के बाद इस तरह के दुस्साहस का बदला लिया और दुनिया को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने दावा किया कि यूपी में पहले दो चरणों के मतदान में सपा और बसपा का सफाया हो गया है और भाजपा तेजी से राज्य में 300 सीटों के करीब पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

गृहमंत्री ने दावा किया कि भाजपा एकमात्र पार्टी है जो गरीबों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि जब मोदी जी कोविड टीका लाए, तो अखिलेश ने इसे मोदी टीका कहा और लोगों से इसे नहीं लेने के लिए कहा। अगर मोदी ने 130 करोड़ लोगों को टीका नहीं दिया होता तो क्या हम तीसरी लहर के दौरान भी उतने ही सुरक्षित होते? भाजपा की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि बुआ-भतीजा (सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव-बसपा अध्यक्ष मायावती) ने 15 साल तक अपनी सरकारें चलाईं लेकिन क्या किसी घर को गैस सिलेंडर मिला, जबकि हमारी सरकार में 1.66 लाख माताओं को सिलेंडर और चूल्हा मिला है और हमने होली और दिपावली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का फैसला किया है।

गर्मी को भाप बनाकर उड़ा देंगे नतीजे : अखिलेश यादव

फतेहपुर, 15 फरवरी (एजेन्सी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 10 मार्च को आने वाले नतीजे 'बाबा मुख्यमंत्री' की गर्मी भाप बन कर उड़ा देंगे।

फतेहपुर के जहानाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने मंगलवार को कहा कि भाजपा जातियों के नाम पर झगड़ा कराना चाहती है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वह पिछड़े और दलितों को धोखा दे रही है। मुस्लिम अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। अगड़ी जातियों के साथ भी अन्याय किया जा रहा है। सपा सरकार के आने पर जातीय जनगणना करायी जायेगी और आबादी के हिसाब से उन्हे हक और सम्मान दिलाने का काम किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, ''बाबा मुख्यमंत्री इन दिनों अपने भाषण बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कानून व्यवस्था से लेकर सपा के लोगों को तमंचावादी तक कह रहे हैं। फतेहपुर की जनता जानती है कि भाजपा के नेता सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जमीन कब्जा करने का काम करते हैं। भाजपा के नेता शराब के धंधे में लिप्त हैं। उनमें सबसे ज्यादा फतेहपुर से ही ताल्लुक रखते हैं। मुख्यमंत्री तो वास्तव में सोए हुए है, जो सो चुके है, उन्हें जगाने के लिए, चिलम वाले लोगों को हटाने के लिए जनता तैयार है। बाबा मुख्यमंत्री की गर्मी को जनता भाप बना कर उड़ा देगी।''

अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल,डीजल के दाम 100 रुपए के पार चए गये हैं। सरसों का तेल महंगा हो गया। किसानों,नौजवानो के साथ सरकार ने धोखा किया। किसानों की आय दोगुनी करने का मामला हो या फिर नौजवानों को नौकरी दिलाने का वादा, सब झूठे साबित हुए हैं। वास्तव में भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है। वहां छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है और सबसे बड़ा नेता सबसे बड़ा झूठ बोलता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कालखंड में दवाई, बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई जाने गई। नए मेडिकल कालेज खंडहर बने हुए हैं, वहां डाक्टर ही नहीं है। सपा सरकार बनने पर मेडिकल कालेजों को और बेहतर बनाएंगे। भाजपा ने अपने कार्यकाल में एक भी नई एबुलेंस नही चलवाई। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के जरिए लोगों पर अन्याय किया गया। उन पर झूठे मुकदमे लादे गए। इसके दोषी बाबा मुख्यमंत्री हैं। सपा सरकार आने पर झूठे मुकदमों को हटा कर पीड़ितों को सम्मान दिया जाएगा।

हिजाब पहनकर कक्षा में जाने की जिद पर अड़ी छात्रा ने परीक्षा छोड़ी

बेंगलुरु, 15 फरवरी (एजेन्सी)। कर्नाटक में हिजाब विवाद अभी तक नहीं सुलझा है। इस बीच मंगलवार को एक छात्रा ने इसलिए अपनी परीक्षा छोड़ दी क्योंकि उसे हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश नहीं मिला। हिजाब विवाद के बीच मंगलवार को कुछ और स्थानों पर हिजाब पहने आई लड़कियों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया।

छात्राओं के आक्रोशित अभिभावकों को स्कूल प्रशासन और पुलिस से तीखी बहस करते देखा गया। एक जगह पर एक छात्र द्वारा भगवा स्कार्फ लहराने की घटना भी सामने आई। पिछले सप्ताह कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में सभी छात्रों को भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब या कोई भी अन्य धार्मिक निशान पहनकर कक्षा में आने पर रोक लगा दी थी।

राज्य में सोमवार से हाई स्कूल खुल गए और स्कूलों में अधिकारियों ने, हिजाब और बुर्का पहनकर आने वाली छात्राओं को अदालत के आदेश का हवाला देकर कक्षा में प्रवेश से मना किया या उन्हें हिजाब उतारने को कहा गया। मंगलवार को शिवमोगा के एक स्कूल में बुर्का पहनकर आई एक छात्रा को हिजाब हटाने को कहा गया तो उसने परीक्षा देने से इनकार कर दिया। लड़की ने संवाददाताओं से कहा, 'हम बचपन से हिजाब पहनते आए हैं और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मैं परीक्षा नहीं दूंगी और घर जाऊंगी।'

चिक्कमगलुरु जिले के इंदवार गांव के एक सरकारी स्कूल में हिजाब पहनकर आई मुस्लिम लड़कियों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया और वापस भेज दिया गया। इसके बाद उसके माता-पिता स्कूल पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जबरन स्कूल परिसर में घुसकर नारेबाजी की और कहा कि उन्हें अदालत का आदेश लिखित रूप में चाहिए। विरोध प्रदर्शन तेज होने पर एक अन्य छात्र ने अपने स्कूल बैग से भगवा स्कार्फ निकाल लिया। छात्र ने शिक्षकों के निर्देश पर स्कार्फ वापस बैग में रख लिया। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रधानाध्यापिका ने दिनभर के लिए स्कूल बंद कर दिया। चिक्कमगलुरु के अन्य संस्थान में हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश नहीं दिए जाने पर तनाव पैदा हो गया।

वहीं, तुमकुरु जिले के एसवीएस स्कूल में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को, हिजाब पहनकर आने पर वापस लौटा दिया गया, जिसके बाद मुस्लिम माता पिता ने स्कूल परिसर में हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर, अदालत के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें शांत किया। इस बीच, उडुपी जिले में छात्राओं के अभिभावकों ने मौलाना आजाद हाई स्कूल के सामने प्रदर्शन कर हिजाब पहनने वाली छात्राओं को अलग कमरे में बैठाने के अधिकारियों के निर्णय का विरोध किया। प्रदर्शनकारी अभिभावकों ने छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षाओं में बैठने देने की मांग उठाई।

साथ ही अभिभावकों ने अधिकारियों से कहा कि अगर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी गई तो वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को इस स्कूल में हिजाब पहनकर आने वाली 20 छात्राओं को अलग कमरे में बैठाए जाने के बाद ये छात्राएं मंगलवार को स्कूल नहीं आईं। हालांकि, मल्लार में सरकारी उर्दू प्राथमिक विद्यालय में हिजाब पहनकर पहुंचीं आठ छात्राओं को परीक्षा देने की अनुमति दी गई।

रीट की जांच को लेकर बीजेपी का विरोध-प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का पैर फ्रैक्चर

जयपुर, 15 फरवरी (एजेन्सी)। रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। उन्हें रोकने के लिए लगाए गए बेरिकेड्स भी उखाड़ कर फेंक दिए। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन से पानी की बौछार की।

प्रदर्शन के दौरान राजेंद्र राठौड़ और सांसद किरोड़ी लाल मीणा कार्यकर्ताओं के साथ बेरिकेड्स की तरफ बढ़े तो पुलिस ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इस दौरान दोनों की पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई। पुलिस प्रदर्शनकारियों को लगातार चेतावनी देते हुए रोकने का प्रयास कर रही थी। उनके नहीं मानने पर राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रदर्शन दौरान धक्का-मुक्की में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। वह न्यूरो केयर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। विरोध-प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र

राठौड़ और सांसद किरोड़ी लाल मीणा, सांसद दिया कुमारी सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भाजपा सांसद दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान के युवाओं साथ अन्याय हुआ है, लेकिन सरकार इस मामले की सीबीआई जांच नहीं करा रही है। सरकार ऐसा क्या छिपा रही है तो इस केस की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जा रही है। भाजपा प्रदेश के लाखों युवाओं को न्याय दिलाने के लिए विरोध कर रही है। हम मामले की सीबीआई जांच नहीं होने तक चुप नहीं बैठेंगे।

भाजपा के बड़े विरोध को देखते हुए पुलिस ने भाजपा कार्यालय से विधानसभा की ओर जाने वाले रास्ते को एक किमी पहले की ब्लॉक कर दिया था। विधानसभा से यह दूर तीन किमी है। यहां त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार थे।

भाजपा के विधानसभा घेराव और मुख्यमंत्री सदन जाने को लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही थी। 22 गोदाम पुलिया के पास पुलिस ने त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग की गई थी। चार हजार पुलिस जवान और दस आईपीएस अधिकारी 22 गोदाम पुलिया पर तैनात थे।

आंदोलन के दौरान किसी भी स्थति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, वज्र वाहन और एंबुलेंस मौके पर मौजूद थे। भाजपा ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की बात कही थी, इसके बाद भी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही थी।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रकः नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com